● वर्ष-3
● अंक-173
रायपुर, बुधवार
28 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बदलते मौसम में इम्यूनिटी ....

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारितः वित्त मंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा-

'वहीं-वहीं दस्तखत हुए, जहां फैसले गलत हुए'

रायपुर. विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित हुआ. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन जैसी थी. राष्ट्रीय औसत से भी कम है. बिहार जैसे पिछड़े राज्य हो या नार्थ ईस्ट के राज्यों से भी खराब स्थिति है. राष्ट्रीय औसत से पीछे हमारी अर्थव्यवस्था है. कृषि क्षेत्र का योगदान 15 फ़ीसदी है. उद्योग का 53 फ़ीसदी है और सर्विस सेक्टर का 31 फ़ीसदी है, जबकि सर्विस सेक्टर में राष्ट्रीय औसत 53 फ़ीसदी है.

मंत्री चौधरी ने कहा, जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ाना सबसे ज़रूरी है. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सिर्फ़ पांच फ़ीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत सात फ़ीसदी है. बीते पांच साल में राज्य का विकास पिछड़ा है. सेकंडरी सेक्टर में भी राष्ट्रीय औसत आठ फ़ीसदी है, जबकि हमारा 7.8 फ़ीसदी है. प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हज़ार और राष्ट्रीय स्तर पर आय 1 लाख 53 हज़ार रुपए है. हमें बहुत ध्यान देकर कम करने की ज़रूरत है. हमें आगामी दस बीस साल की योजना पर काम करने की ज़रूरत है.

चौधरी ने आगे कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना की है, वैसे ही हमने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है. 1 नवम्बर 2024 को हम विजन @2047 की कल्पना जारी करेंगे. छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे. विजन डक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की विजन को भी शामिल करेंगे. पांच लाख करोड़ की जीडीपी को हम दस लाख करोड़ तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम राज्य के हर

वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. हमने दस पिलर के आधार पर बजट पेश किया है.

उन्होंने कहा, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब उसी वित्तीय वर्ष में 11 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया था. हमारी सरकार आई तो हमने अपने पहले वित्तीय वर्ष में 13 हज़ार करोड़ का लोन लिया है. यह लोन किसानों, महिलाओं और आवास के लिए लिया है. इसी वित्तीय वर्ष में हमने 21 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया है. कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक बजट में ही हमने 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया था. आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे

उसी दिन हम महतारी वंदन योजना और कृषक कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में एक साथ देने की स्थिति में हैं.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, इंदिरा गांधी के समय महंगाई दर 28 फ़ीसदी तक चली गई थी. मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है उससे यह देश कभी भी महंगाई दर में फंसने वाला नहीं है. महतारी वंदन योजना के लिए साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये के प्रावधान करने पर कांग्रेस ने खूब दुष्प्रचार किया कि हम देंगे या नहीं. कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान दस लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था. कुल पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत थी. अपनी सरकार के आख़िरी साल में बजट सिर्फ़ साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया. पूरा प्रदेश जानता है कि जन घोषणा पत्र में किसने क्या कहा था और क्या किया. कांग्रेस ने ये भी वादा किया था कि महिलाओं को छह हज़ार रुपये दिया जाएगा, मगर छह रुपये तक का भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग में 130 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है, खनिज साधन विभाग में 80 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है, पीएचई में 90 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. डीएमएफ के पैसे से जेल रोड की बिल्डिंग से कैसे पूरे राज्य में काम किया जाता था ये सभी जानते हैं. आज़ादी के 70 सालों तक कांग्रेस ने डीएमएफ़ के बारे में सोचा नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमएफ लाकर 30 फ़ीसदी राशि स्थानीय विकास के लिए दिये जाने का नियम बनाया. आवास में हमने आठ हज़ार तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया है. इससे पंचायत विभाग के बजट में 70 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है. स्कूल शिक्षा विभाग में जीतने बिल्डिंग इस बजट में लिया गया इतना इतिहास में कभी नहीं लिया गया. रामलला के दर्शन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है.

मंत्री चौधरी ने आगे कहा, भय, लोभ की आड़ में होने वाले धर्मांतरण को रोकने सरकार प्रतिबद्ध है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर लेने का वादा हमने पूरा किया है. प्रति मानक बोरा 5500 रुपये की दर पर भुगतान किया जायेगा. आवास प्लस की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा ने किया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस सर्वे सूची को मानने से इंकार कर दिया था. 2011 की सूची को मानने से इंकार कर दिया था. यूपीए की सरकार ने ये बनाया था. क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं था. पीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच कराने हम प्रतिबद्ध है. सीबीआई जांच कराई जा रही है. यूपीएससी की तर्ज़ पर पीएससी की परीक्षा कराने की तैयारी हम करने जा रहे हैं. बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए.

रास चुनावः उप्र की 8 सीटों पर बीजेपी की जीत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से खेला हुआ है। इस खेल की वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे। बीजेपी से आठ और समाजवादी पार्टी से तीन उम्मीदवार को मैदान में उतर गया था। समाजवादी पार्टी के विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से भाजपा को अपने आठवी उम्मीदवार को जीत दिलाने में मदद मिली है। भाजपा की ओर से जिन आठ उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है उसमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और आठवें उम्मीदवार संजय सेठ शामिल है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन और रामजीलाल सुमन को जीत मिली है। आलोक रंजन को संजय सेठ ने हराया है। भाजपा ने इसे नरेंद्र मोदी अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की जीत बताया है। भाजपा ने इसे अपने विचारधारा की जीत बताया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे दिन राजनीतिक हलचल तेज रही। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बाद आप भी लगाया है।

हिमाचल में कांग्रेस को मिली हार

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक उठा पटक देखने को मिली। 40 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार मिली। भाजपा के हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा

चुनाव के लिए आज वोट डाले गए थे। कांग्रेस के नौ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जिसकी वजह से भाजपा को जीत मिली है। हर्ष महाजन ने इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नगर का धन्यवाद किया है।

सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस ने हमारे 5-6 विधायकों का किया अपहरणः सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर सीआरपीएफ बसों का इस्तेमाल कर विधायकों को शिफ्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस पांच-छह विधायकों को ले गई है। ये आरोप राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गिनती शुरू हो गई है और विपक्षी नेता बार-बार मतदान अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है...उन्होंने काफी देर तक गिनती रोकी रखी थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं हिमाचल भाजपा इकाई के नेताओं से आग्रह करता हूं - धैर्य रखें, लोगों पर दबाव न डालें। उन्होंने दावा किया कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस का काफिला 5-6 विधायकों को ले गया है। मैं कह सकता हूं कि जो लोग चले गए हैं, उनसे उनके परिवार वाले संपर्क कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार से संपर्क करें.

कर्नाटकः कांग्रेस के तीनों रास उम्मीदवार जीते, भाजपा का एक प्रत्याशी विजयी

नई दिल्ली। मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक से कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों और बीजेपी के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की। राज्य की चार राज्यसभा सीटों के लिए पांच उम्मीदवार थे। कांग्रेस के सभी तीन उम्मीदवार - पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, और वर्तमान राज्यसभा सांसद सैयद

नासिर हुसैन और जी सी चंद्रशेखर - जीते, भाजपा उम्मीदवार और पूर्व एमएलसी नारायणसा भांडगे चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं, जद (एस) के उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी हार गए। बीजेपी-जेडीएस गठबंधन को झटका लगा क्योंकि कम से कम एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर क्रमशः 47, 46 और 46 वोट हासिल करके विजयी हुए और अब राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मतदान प्रक्रिया 99.5 प्रतिशत मतदान के साथ संपन्न हुई, क्योंकि कुल 223 मतदाताओं में से 222 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि यह कांग्रेस की एकता और अखंडता को दर्शाता है। मैं सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया को धन्यवाद देता हूं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। मैं सभी मतदाताओं, सीएम और पार्टी कार्यकर्ताओं और एआईसीसी अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद देना चाहता हूं।

बीजेपी-जेडीएस गठबंधन की ओर से पांचवा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर खेला करने की कोशिश की थी। हालांकि, यह सफल नहीं हो पाया। कर्नाटक की 223 सदस्यीय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर कांग्रेस के पास 133 विधायक हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) के पास क्रमशः 66 और 19 विधायक हैं। अन्य विधायकों की संख्या चार है। राज्यसभा की चार सीट इसके चार सदस्यों - केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (भाजपा) और कांग्रेस के जी सी चंद्रशेखर, सैयद नसीर हुसैन और एल हनुमंतैया की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुई है।

प्रमुख समाचार

लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीसीए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से

पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2019 में लागू हुआ सीएए इस संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए थे। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा अधिनियमित सीएए, पूरे भारत में गहन बहस और व्यापक विरोध का विषय रहा है। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए फास्ट-ट्रैक मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है.

आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतिःशाह

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आज जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी, 2019 को गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। शाह ने आगे लिखा कि संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है।

देश के भविष्य की दुश्मन बन गई है मोदी सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को पेपर लीक रोकने में विफलता को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और उस पर देश के भविष्य का दुश्मन बनने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे सरकार पर नौकरी पैदा करने वाले संस्थानों को अपने दोस्तों को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार 'देश के भविष्य' की दुश्मन बन गई है! कहीं भर्ती के लिए तरसते छात्र, कहीं पेपर लीक से हताश छात्र, कहीं नियुक्ति के लिए कोर्ट का चक्कर काटते छात्र तो कहीं आवाज़ उठाने पर लाठियों की मार सहते छात्र। RO-ARO से लेकर पुलिस भर्ती तक और रेलवे से लेकर सेना तक एक भी परीक्षा न्यायपूर्ण ढंग से करा पाने में नाकाम भाजपा सरकार अपना गुस्सा युवाओं पर निकाल रही है। राहुल ने आगे लिखा कि नौकरी पैदा करने वाले संस्थान अपने मित्रों को बेच कर युवाओं को ठेके पर रखना, मोदी की पॉलिसी है और शोषण मोदी की गारंटी। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर लगा ग्रहण है.

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अवमानना का नोटिस थमाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अपने औषधीय उत्पादों का विज्ञापन करने से रोक दिया और नवंबर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। हम रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करते हैं। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। एलडी वकील उनकी ओर से नोटिस स्वीकार कर 2 सप्ताह के भीतर उत्तर दें। शीर्ष अदालत ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन जारी न करे या एलोपैथी के प्रतिकूल बयान न दे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को अगले आदेश तक नियमों के अनुसार बीमारियों/बीमारियों के इलाज के रूप में निर्दिष्ट उनके विपणन किए गए औषधीय उत्पादों के विज्ञापन और ब्रांडिंग से रोका जाता है। उन्हें प्रिंट या अन्य मीडिया में किसी भी रूप में किसी भी चिकित्सा प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से सावधान किया जाता है।

2.5 करोड़ देकर यूएई की जेल में बंद 900 भारतीयों को छुड़वाया

यूएई। भारतीय व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति ने 2024 की शुरुआत से खाड़ी देश की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 1 मिलियन दिरहम (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) का दान दिया। उनका लक्ष्य इस वर्ष 3,000 कैदियों को रिहा कराना है। प्योर गोल्ड ज्वैलर्स के 66 वर्षीय मालिक फिरोज मर्चेंट ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों को 1 मिलियन दिरहम का दान दिया। वह दुबई में स्थित है। फिरोज मर्चेंट के कार्यालय ने कहा, यह रमज़ान से पहले विनम्रता, मानवता, क्षमा और दयालुता का संदेश है। उनके कार्यालय के बयान में कहा गया है कि दुबई स्थित प्रमुख भारतीय व्यवसायी और प्योर गोल्ड के परोपकारी फिरोज मर्चेंट ने अरब देश की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए करीब 2.25 करोड़ (एईडी 1 मिलियन) का दान दिया है। मर्चेंट अपनी द फॉरगॉटन सोसाइटी पहल के लिए जाने जाते हैं, 2024 की शुरुआत से पहले ही 900 कैदियों की रिहाई की सुविधा प्रदान कर चुके हैं।

क्या भाजपा को चुनौती दे पाएगा सपा-कांग्रेस अलायंस

नदीम

ना-ना करते बात हां-हां में बदल गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (एसपी) की 17 सीटों के ऑफर को मंजूर कर ही लिया। या यूं कहें कि उसे मंजूर करना ही पड़ा। वही कांग्रेस जो पहले यूपी में 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाते हुए दो दर्जन से कम सीटों कोई बात सुनने को तैयार नहीं थीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले अपने प्रत्याशियों के एलान, फिर कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ने की घोषणा को 'अधिकृत' नहीं मान रही थी। जिसके कई नेता मीडिया में यह स्थापित करने में जुटे थे कि दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं, उसी पार्टी ने न केवल संख्या में 17 सीटें बल्कि 17 में भी वो सीटें जो समाजवादी पार्टी ने अपने सुविधानुसार दीं, स्वीकार कर लिया। और, अब उसे भाजपा को हराने की दिशा में उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम बता रही है।

कांग्रेस के मन बदलने की दो बड़ी वजहें हैं। एक यह कि कांग्रेस को जमीनी हकीकत का अंदाजा है। लड़ने को 80 सीटों पर भी लड़ा जा सकता है। 2019 में पार्टी ने यही किया था, लेकिन जीत मिली सिर्फ एक सीट पर। राहुल गांधी भी हार गए थे। दूसरी वजह, कांग्रेस की उम्मीद बीएसपी से जुड़ी हुई थी, लेकिन वह समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं, सपा ने 17 सीटें ऑफर कर 'लास्ट एंड फाइनल कॉल' के मोड में आ गई। कांग्रेस को लगा कि अगर यह मौका भी गया तो यूपी में उसका कोई सहारा नहीं होगा। यूपी में भाजपा के खिलाफ अगर कोई विकल्प के रूप में जाना जाता है तो वह सपा ही है। कांग्रेस तो राज्य में हाशिए पर ही है। बीएसपी की हालत भी कुछ वैसी ही है। 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सदस्यों के सदन में उसका सिर्फ एक प्रत्याशी जीत पाया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में सपा से गठबंधन में उसे दस सीटों पर जीत मिली थी। मुख्य विपक्षी दल के नाते सपा के लिए जरूरी था कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता हो।

चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल भी सपा का साथ छोड़ भाजपा के संग चला गया। बीएसपी के साथ गठबंधन न करने का एलान पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में उसे लगा कि अगर कांग्रेस के प्रति भी अड़ियल रवैया रहा तो भाजपा के खिलाफ एकजुटता न हो पाने का ठीकरा उसके सिर ही फूट जाएगा। खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, जिसे सपा का कोर वोटर समझा जाता है। 2019 में कांग्रेस एक सीट जीती और तीन पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। सपा पहले कांग्रेस को 11 सीटें ही देना चाहती थी। रायबरेली और अमेठी में वह पहले से उम्मीदवार नहीं उतारती है। इस तरह से कांग्रेस की 13 सीटें हो रहीं थी। सात राष्ट्रीय लोकदल के लिए थीं। बची 60 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखी थीं। जब राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं रहा तो सात सीटें और बच गईं। इसी वजह से कांग्रेस को 17 सीटें मिल गईं।

कांग्रेस हाल-फिलहाल के वर्षों में जब भी किसी दल के साथ गठबंधन के लिए बात करती है तो वह यूपी के 2009 लोकसभा चुनाव को बेस बनाने की जिद करने लग जाती थी। 2024 के लिए भी यही हो रहा था। दरअसल, 90 के दशक से कांग्रेस जब यूपी से बेदखल हुई तो 2009 ही एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव रहा, जिसमें उसका प्रदर्शन करिश्माई रहा है। उसने तब राज्य में 21 संसदीय सीटें जीती थीं, बीएसपी से भी एक ज्यादा। उस साल सपा को 23 सीटों पर जीत मिली थी। सपा और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का क्या असर होगा? इसका जवाब है किभाजपा के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो या ना हो, लेकिन बीएसपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी।

वजह यह है कि मुस्लिम वोटों का रूझान इस गठबंधन के साथ हो सकता है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर बीएसपी को होगा। बीएसपी मुस्लिम बाहुल सीटों पर मजबूत मुस्लिम चेहरों के साथ चुनाव में उतरने की योजना बना रही है।

यह मानी हुई बात है कि कांग्रेस के पास यूपी में अपना कोई वोट नहीं है। जो कुछ भी है, वह सपा का ही है। गठबंधन में भी उसे ही भाजपा के मुकाबले अपनी ताकत झोंकनी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन एक बार फिर गठबंधन कर अखिलेश यादव ने यह धारणा बनने से रोका कि कांग्रेस को साथ रखने का प्रयास न करके उन्होंने भाजपा को मजबूती दी। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और बीएसपी का गठबंधन था, जिसे वोटों के गणित के हिसाब से सबसे मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। लेकिन राजनीति में 2+2=4 नहीं होता।

रामायणी सांसद के तमगे वाले आदर्श गांव की बदहाल स्थिति

बालोद। विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण लेकर सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने हैं सांसद तरह-तरह से अपना पीआर बढ़ाने में लगे हुए हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बालोद जिले का सांसद आदर्श ग्राम अरमरी कला जहां पर महज तीन दिन पहले ही सांसद आदर्श ग्राम का बोर्ड लगाया गया है। गांव के सरपंच सहित आम जनता ने संसद के गांव के प्रति रवैया के लेकर कड़ी आलोचना की है ग्रामीणों का आरोप है कि, सासंद मोहन मांडवी इस रास्ते से कई बार गुजरते हैं परंतु अपने गोद लिए हुए ग्राम का सुध तक नहीं लेते।

पूरे मामले पर सांसद मोहन मंडावी का कहना है कि आदर्श गांव के रूप में हमने गोद लिया था, लेकिन यहां सभी चीजों को करना सरपंच का काम होता है सरपंच को आना चाहिए उन्होंने कहा इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उन्होंने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि इसे मोदी का गांव बोलकर जानबूझ कर कांग्रेस वालों ने उपेक्षित किया है। अब सवाल यह उठता है कि रामायणी सांसद होने का खिताब प्राप्त कर चुके मोहन मांडवी क्या रामचरितमानस के भरोसे एक बार फिर से टिकट लेकर आएंगे और टिकट लेकर आ भी गए तो क्या वह जीत पाएंगे। यह गांव वैसे तो शुरू से ही विकसित गांव की श्रेणी में आता है यहां पर विद्यालय से लेकर महाविद्यालय पहले से ही बने हुए हैं।

ग्राम के सरपंच तीजू राम मंडावी ने कहा कि जब हमारे गांव को सांसद आदर्श गांव के नाम पर प्रस्तावित किया गया तो हमें लगा कि गांव का चहुमुखी विकास होगा परंतु सांसद कुछ बार तो आए पर गांव को विकास की दृष्टिकोण से हमेशा ऊपेक्षित रखा, हमने तालाब सौंदर्यकरण से लेकर यात्री प्रतीक्षालय और भी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार सांसद मोहन मांडवी को दस्तावेज देते रहे परंतु उन्होंने हमारी बातों को सिरे से नकार दिया। सांसद प्रतिनिधि वासुदेव मारकण्डे ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम का एक अलग पहचान होता है। वह पहचान इस गांव को कभी मिल ही नहीं पाई और विकास जो है वह लोगों के बीच दिखता है। जब सांसद जीतकर आए तो उन्होंने इस गांव को अपना गोद ग्राम बनाया, हमें बड़ी खुशी हुई मुझे प्रतिनिधि बनाया गया परंतु उसके बाद उनकी कृपादृष्टि इस गांव पर बेहद कम रही। बहरहाल सांसद मोहन मांडवी गांव-गांव रामचरितमानस बांट रहे हैं लेकिन इस चुनाव में यह देखना लाजमी होगा कि प्रभु श्रीराम के सहारे वे टिकट पाने और जीतने में कामयाब होत हैं या नहीं।

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, चार माओवादी ढेर

बीजापुर। बीजापुर में मंगलवार की सुबह सुरक्षाबलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली हैं। जांगला थाना क्षेत्र के बड़ेतुंगाली व छोटेटूंगाली के जंगलों में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने चार नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की हैं। वही जवानों द्वारा मौके से नक्सलियों के हथियार व अन्य सामान बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जांगला थाना क्षेत्र के बड़े तुंगाली व छोटेतुंगाली के जंगलों में कंपनी नंबर दो के प्लाटून कमाण्डर, जनताना सरकार अध्यक्ष व भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीआरपीएफ, डीआरजी व बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

अभियान के दौरान मंगलवार की सुबह बड़े तुंगाली और छोटेतुंगाली के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गये और मौके से हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इलाके में सर्चिंग जारी हैं।

अतिसंवेदनशील बोदली ग्राम में शुरू हुआ विकास कार्य

ग्रामीणों को मिल रही है राशन समेत हर सुविधा

जगदलपुर। बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड अंतर्गत अतिसंवेदनशील बोदली इलाके में शासन की नियद नेल्लानार योजना से अब विकास का उजियारा होने लगा है, जिला प्रशासन द्वारा इस बेहद संवेदनशील इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन दुकान आदि मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने व्यापक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। जिससे उक्त दूरस्थ संवेदनशील क्षेत्र में विकास कार्यों से बदलाव की बयार परिलक्षित हो रही है। अभी हाल ही में गांव में राशन दुकान प्रारंभ कर खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामग्रियों का भंडारण किया गया है।

साथ ही गांव में नवीन ग्राम पंचायत भवन,उप स्वास्थ्य केन्द्र,प्राथमिक शाला भवन तथा सड़क-पुलिया निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है, ग्राम पंचायत बोदली जिला मुख्यालय से लगभग 110 की दूरी पर स्थित है, जिसका पहुंच मार्ग दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से होकर जाना होता है, इसके आश्रित गांव में सालेपाल, कहचेनार और टेटम है और कुल जनसंख्या लगभग 1041 है, जिले के इस दूरस्थ ईलाके में राशन दुकान शुरू होने से ग्रामीणों को अब गांव में चावल सहित शक्कर, चना, गुड़, नमक इत्यादि जरूरी सामग्रियां सुलभ हो रही है।

गांव में राशन दुकान शुरू होने से अब ग्रामीण उत्साहित हैं कि उन्हें खाद्यान्न और अन्य दैनिक जरूरत

के सामानों की पूर्ति के लिए सुविधा होगी। वहीं स्वास्थ्य केन्द्र बनने के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी। इस बारे में गांव के पटेल पाण्डेराम बताते हैं कि पहले बसाहट से करीब दो किलोमीटर दूर बोदली पुलिस कैम्प के समीप अस्थायी रूप से राशन दुकान संचालित किया जा रहा था,जिससे खेतों को पगडण्डी से पार कर खाद्यान्न एवं जरूरी सामान लेने जाने में दिक्कत होती थी लेकिन अब गांव में राशन दुकान प्रारंभ होने पर उक्त समस्या से निजात मिल गई है। मुख्य सड़क से राशन दुकान तक मिट्टी-मुरम सड़क एवं पुलिया निर्माण होने से अब मुख्य बसाहट तक बारिश में भी सुगम आवाजाही कर सकते हैं। बोदली ग्राम पंचायत के लिए नया भवन पूर्ण होने के फलस्वरूप अब गांव वालों को अपने गांव के विकास लिए नई ईबारत गढ़ने हेतु सार्वजनिक स्थल सुलभ हो गया है।

बदल जाएगा बालोद रेलवे स्टेशन, तीन ओवरब्रिज, मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

बालोद। भारतीय रेल ने बालोद जिले में महत्वपूर्ण सौगात दी है। जिले के दल्ली राजहरा स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री ने रखी। वहीं सांसद मोहन मांडवी इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि मोदी की गारंटी है जो पूरी होने जा रही है। रेलवे के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया है। सरकार रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत आज का यह शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है।

शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में बालोद जिले को महत्वपूर्ण सौभाग्य मिली। जिसमें मॉडल स्टेशन के अलावा काफी लंबे समय से मांग थी कि पाररास रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए इसकी आधार शिला रखी गई है। वहीं चैनगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरब्रिज और परसोदा के पास ब्रिज की आधारशिला रखी गई है। जिन जगहों पर इस निर्माण के आधारशिला रखी गई है। वह काफी व्यस्ततम मार्ग है। रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण फाटक बंद होने से राहगीरों को दिक्कतें होती थी।

सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को निर्देशित किया कि राजहरा शहर को लेकर विशेष ध्यान दें। साथ ही उन्होंने दो पानी टैंकर देने की निर्देश भी जिला इस्पात संयंत्र प्रबंधन को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह लाइन डबल लाइन बने और यहां पर एक एसी कोच की भी शुरुआत हो। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र को सीधे-सीधे डोंगरगढ़ से जोड़ने की भी बात कही है।

उन्होंने कहा फिर जब लौट कर आएंगे। जब आपका आशीर्वाद रहेगा तब बचे हुए कामों को पूरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जरूर पूरी होती है। इस आयोजन में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन साहू पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार यज्ञ दत्त शर्मा प्रमोद जैन सहित अन्य मौजूद रहे।

तपती गर्मी मे कैसे बुझेगी प्यास

बिगड़े हैण्डपम्प को सुधारने के लिए न मैकेनिक और न ही साधन

बीजापुर। तपती गर्मी मे कैसे बुझेगी प्यास इस बात की चिंता बीजापुर के ग्रामीणों को सताने लगी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न मदों से उत्खनन किये गए अधिकांश हैंडपंप उचित रख-रखाव के अभाव मे बिगड़े पड़े हैं इन बिगड़े पड़े हैंडपंपों को समय रहते सुधारने की चिंता न तो विभाग को है ओर न ही जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे मे आने वाली भीषण गर्मी मे होने वाले जल संकट को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यह बात बीजापुर जिले के भोपालपटनम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य बसंत राव ताटी ने कही हैं।

जिला पंचायत सदस्य ताटी का कहना है भोपालपटनम विकासखंड मे जगह जगह हैंडपंप बिगड़े पड़े हैं, लेकिन इन्हे सुधारने के लिए स्वयं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी अपने हाथ खड़े कर दिए है। उन्होंने बताया की बिगड़े हैंडपंपो को सुधारने के लिए जब सम्बंधित विभाग से सम्पर्क किया जाता है, तो रटा-रटाया एक ही जवाब मिलता है की

हैंडपंप मे लगे पाइप वर्षो पुराने होने की वजह से सड गए है इन हैण्डपंपो में जब तक नये पाइप नहीं डाले जाएंगे तब तक इन्हे सुधार पाना मुश्किल है।

ताटी ने बतया की क्षेत्र मे अधिकांश हैंडपम्प ऐसे हैं जो की कई वर्ष पुराने हैं। जिन्हे तत्काल सुधारने की अवश्यकता है। लेकिन सम्बंधित विभाग का कहना है कि इन बिगड़े हैंडपंपो को सुधारने के लिए विभाग के पास मेकनिकों की कमी होने के साथ-साथ इन्हे पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों मे आने वाले भीषण गर्मी मे ग्रामीणों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

बिलासपुर कानन के लिए सीजेडए की हामी अब दिल्ली से आएंगे गोराल, बदले में देंगे चौसिंगा

बिलासपुर। कानन पेंडारी जू पर्यटक जल्द ही गोराल (पहाड़ी बकरा-बकरी) देख पाएंगे। केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण इसकी अनुमति दे दी है। गोराल के बदले में कानन प्रबंधन चार चौसिंगा देने का निर्णय लिया है। होली पर्व के पहले वन्य प्राणियों की अदला-बदली की इस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। गोराल लेकर दिल्ली जू का दल बिलासपुर पहुंचेगा। चौसिंगा की डिमांड दिल्ली जू से कानन पेंडारी जू प्रबंधन को आया था। दरअसल कानन में यह प्रजाति सरप्लस है। यहीं कारण ही लगातार जहां-जहां से मांग आ रही है, उन्हें सहमति दे दी जा रही है। चौसिंगा के बदले कानन प्रबंधन ने दिल्ली से गोराल मांगा। वर्तमान में यह प्रजाति कम है। इनका कुनबा भी नहीं बढ़ रहा है। इसे देखते हुए कानन प्रबंधन उनके समक्ष यह मांग रखी थी, जिस पर उन्होंने सहजता के साथ स्वीकृति दे दी। लेकिन, दो जू प्रबंधन के बीच आपसी समझौते के बाद वन्य प्राणियों की अदला-बदली नहीं की जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति लेनी होती है।

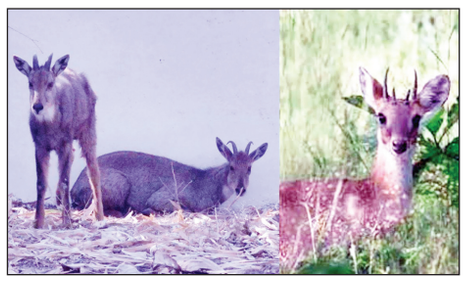

यही कारण दोनों जू ने आपसी सहमति के साथ अदला-बदली के लिए स्वीकृति मांगी। जिस पर प्राधिकरण की समिति ने सहमति की मुहर लगा दी है। इसके साथ दोनों जू को इसकी जानकारी भी भेजी है। अब दोनों जू प्रबंधन आपस में एक तिथि निर्धारित करेंगे। इस तिथि में वन्य प्राणियों की अदला-बदली की जाएगी। कानन प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली जू का दल ही गोराल लेकर बिलासपुर आएगा। प्रयास किया जाएगा कि यह प्रक्रिया होली पर्व के पहले ही पूरी कर ली जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पर्व के बाद इसे पूरा किया जाएगा। मालूम हो कि देशभर के जू अपने-अपने जू के सरप्लस वन्य प्राणियों की रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजते हैं। इस रिपोर्ट को वहां के डायरेक्टर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जिन्हें जिन वन्य प्राणियों की आवश्यकता है, उनसे डिमांड कर सकते हैं। चौसिंगा की डिमांड भी दिल्ली जू प्रबंधन ने यही देखकर भेजी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस्तर से जबलपुर-दिल्ली के लिए जल्द मिलेगी फ्लाइट की सुविधा

जगदलपुर। बस्तर के लोगों को जल्द ही जबलपुर और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए एयर एलायंस के प्रस्ताव को डीजीसीए ने स्वीकार कर लिया है। नए रूट पर हवाई सेवा चालू करने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल एयरलाइंस जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट सेवाएं दे रही। बस्तर के लोग लंबे समय से दिल्ली और जबलपुर रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए रूट में फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए के आलावा राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दस्तावेजों के अलावा एयरपोर्ट में जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि एयरपोर्ट में बे एरिया और अप्रेन एरिया बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही रनवे को दोनों छोर से फ्लाइट उतरने के लिए तैयार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम जशपुर में हुई झमाझम बारिश

जशपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जशपुर के बगीचा, पंडरापाठ, सन्ना सहित पठारी इलाका और बलरामपुर क्षेत्र में आज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है। बेमौसम बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इससे रबी फसलों को नुकसान का खतरा है। वहीं बेमौसम बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में यलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 5 दिन के लिए प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। सोमवार को कोरबा जिला 34।9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं सबसे कम अंबिकापुर में 14 डिग्री टेंपरेचर दर्ज किया गया।

भाटापारा में बढ़ता अपराध पुलिस पर उठे सवाल

भाटापारा। भाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अपराध और असामाजिक तत्वों का डेरा बढ़ता ही जा रहा है। भाटापारा को छोटे मुंबई और सट्टे का गढ़ माना जाता है भाटापारा में दूर दराज से लोग अपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी के नियत से भाटापारा पहुंचते हैं। कोई इसमें सफल होता है तो कोई अपनी संपत्ति व अपनों को खो देता है। हर गली मोहल्ले में अवैध शराब के कोचियों को शराब बेचते देखे जा सकते हैं। ऐसे ही आधी रात के बाद शहर के कुछ होटल में शहर और बाहर अन्य जिलों से आए रसूखदारों की रात रंगीन करने कॉल गर्ल को देखा जा सकता है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के लिए कोचिए और छोटे खाईवाल पर ही शिकंजा कसता है। जबकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में माफिया वह बड़े खाईवाल सक्रिय होकर अपने काम को बेझिझक अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों की शिकायत आए दिन सुनने को मिलती है। पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने कहा इस संबंध में जिला बलौदा बाजार के उप पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है।

मुर्गियों से भरा वाहन पेड़ से टकराया, चालक घायल

जगदलपुर। जगदलपुर एनएच 30 में बीती रात मुर्गियों से भरी पिकअप पेड़ से जा टकराई, इस दुर्घटना में जहां परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घटना के बारे में बताया गया कि पिकअप वाहन धमतरी से कोंडागांव की ओर आ रही थी। मिली जानकारी के अनुसार धमतरी निवासी लक्की नागरची और ईश्वर साहू चालक ग्राम हरनचिरई निवासी दोनो पिकअप वाहन में सवार होकर धमतरी से मुर्गी लेकर जगदलपुर डिलवरी करने के लिये आ रहे थे, इसी दौरान नेशनल हाइवे पर झूलनाडीही के पास रोड किनारे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे मे लक्की की मौके पर ही मौत हो गई वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बेहतर उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं इस घटना में वाहन में भारी हुई कइयों मुर्गियां भी हादसे के चलते उनकी मौत हुई है। फरसगांव पुलिस मौके पर पहुँच जांच शुरू कर दी है।

बीमार शख्स को गांव के तीन युवकों ने जमकर पीटा

कोरबा। कोरबा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। तीन युवकों ने पीट-पीट युवक का हाथ तोड़ दिया, हद तो तब हो गई जब पीटते-पीटते जलती हुई आग में युवक बेहोश हो कर जा गिरा। युवक की सरेआम गांव के बीच तीन युवकों ने की पिटाई लेकिन किसी ने भी बचाने का प्रयास नही किया। युवक के बेहोश होने पर मरा हुआ समझकर मारपीट करने वाले युवक भाग खड़े हुए। घायल युवक को परिजनों ने तत्काल 112 की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां उसका उपचार जारी है। ये घटना बांगो थाना अंतर्गत गढ़ उपरोड़ा की है जहां घायल युवक 29 वर्षीय संतोष कुमार के साथ घटी है। घायल संतोष की पत्नी लक्ष्मीबाई ने बताया कि पिछले तीन दिनों से संतोष की तबीयत ठीक नहीं है संतोष अजीबोगरीब हरकत किया करता है, लक्ष्मी ने बताया कि उसे किसी काले साये का असर है जिसके चलते हुए हरकत करता है। गांव में ही रहने वाले तीन युवकों ने लात डंडे और घुसे से पीटना शुरू किया जहां पीट-पीट कर उसका एक हाथ तोड़ दिया।

महिला आयोग ने उत्पीड़न से संबंधित 15 मामलों पर की सुनवाई

■ **कलेक्टर को दिए निर्देश**

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की न्याय पीठ द्वारा आज आदिजाति कल्याण सभाकक्ष दत्तात्रेय, गौरेला में महिला उत्पीड़न से संबंधित 15 प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पक्षकारों को समक्ष प्रकरणों को सुना और आपसी समझौता के दो प्रकरणों पर समझौता पत्र पर दोनों पक्ष से हस्ताक्षर कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। वहीं सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य डॉ. अर्चना उपाध्याय, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे,उप पुलिस अधीक्षक श्मीरा अग्रवाल भी उपस्थित थी।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला स्तर पर चौथी सुनवाई हुई। उन्होंने गाली-गलौज, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, लैंगिक उत्पीड़न, वित्तीय लेनदेन आदि से संबंधित प्रकरणों की और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने जिला प्रशासन को तीन माह का समय दिया है।

इसी तरह जिले में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने सुनवाई में उपस्थित अपर कलेक्टर को निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रकरण में लोक निर्माण विभाग में केयरटेकर के पद पर कार्यरत आवेदिका और दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर आपरेटर अनावेदक का रहा। आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ महिला उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।

यह मामला आंतरिक परिवाद समिति की जांच के विषय है। दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने पर पता चला कि अनावेदक ने भी विभाग में शिकायत प्रस्तुत किया है। लेकिन दोनों पक्षों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दोनों पक्ष पीडब्लूडी विभाग के ईएनसी कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी है और अब तक कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं हुआ है। आयोग ने मामला की गंभीरता को देखते हुए। इस मामला में आयोग ने अपर कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी।

जिला मुख्यालय में उपरोक्त कानून के तहत जिला परिवाद समिति का गठन तत्काल कराया जाये। यह परिवाद समिति जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के शासकीय एवं अशासकीय सभी संस्थानों पर कराया जाना है। जिसके लिए अपर कलेक्टर को दो माह के भीतर परिवाद समिति का गठन कर आयोग को सूचना देने लिए कहा गया। इस प्रकरण में तीन माह के भीतर जांच करा कर प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करने के लिए कहा गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका का पति आठ माह पहले दूसरी पत्नी बना ली। उसे हिस्सा नहीं दे रहा है। आवेदिका को पता नहीं है कि इसका कितना जमीन है और प्रकरण न्यायालय से संपत्ति दिलाने के योग्य होने से आयोग द्वारा नस्तीबद्ध किया गया।

भाजपा नेता पर नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोप

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि भाजपा के जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह नहरेल उर्फ भोलू और उनकी पत्नी मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल पर लगा है। दोनों पर मरवाही जनपद पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने का आरोप लगा है। मरवाही के रहने वाले पीड़ित मुकेश मानिकपुरी की शिकायत के बाद मरवाही थाना पुलिस दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक, मुकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2022 में मरवाही जनपद पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगवाने के एवज में उसने बीजेपी नेता योगेंद्र सिंह नहरेल उर्फ भोलू को 1 लाख रुपये दिए थे। जिसमें 40 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर और 60 हजार रुपये नगद दिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब उसकी नौकरी को लेकर कुछ नहीं हुआ तब उसने योगेन्द्र नहरेल से इस बारे में बात की, लेकिन योगेंद्र उसे टालमटोल जवाब देकर गुमराह करने लगा।

पीड़ित मुकेश ने पुलिस को आगे बताया कि काफी दिनों तक योगेंद्र उसे गुमराह करता रहा, लेकिन जब उसे ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने योगेंद्र से अपने पैसे वापस देने की मांग की। जिसके बाद योगेंद्र ने अपनी सरपंच पत्नी प्रियदर्शनी नहरेल के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उसे एक झूठे मामले में फंसाने का प्रयास भी किया। जिससे उसकी छवि समाज में इस प्रकार धूमिल हो गयी कि अब उसे दूसरे स्थान में रहकर जीविका उपार्जन पड़ रहा है।

एसडीओपी श्याम सिदार ने बताया कि दो साल पुराने इस धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित मुकेश मानिकपुरी की शिकायत के बाद भाजपा के जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह नहरेल उर्फ भोलू और उनकी पत्नी मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल के खिलाफ 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

आपराधिक घटनाओं पर गर्माया सदन, हंगामा के चलते बाधित हुई कार्यवाही

■ विपक्ष ने स्थगन पेश कर कहा 'अमृतकाल विषकाल बन रहा'

रायपुर। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की। स्पीकर डॉ। रमन सिंह के स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए हंगामा मचाया। इस पर आसंदी ने पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से हंगामा मचाते हुए गर्भगृह में उतर गए। इस पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए एक बार फिर सदन स्थगित की गई। आखिर में निलंबन समाप्त करने के बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई।

इससे पहले उमेश पटेल और विक्रम मंडावी ने कहा कि विधानसभा के क़रीब ही हत्या हो गई। उत्तरप्रदेश से पिस्टल लाया गया। कवर्धा में हत्या हो रही है। कवासी लखमा ने कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में हत्याएं हुई है। नारायणपुर में दुर्ग के एक व्यापारी को बाजार में काट दिया गया। हमारी सरकार में भी घटनाएं होती थी, लेकिन हर दिन इस तरह से घटनाएं नहीं हुई। सुरक्षा राज्य की सबसे बड़ी चीज़ है। ना रायपुर ना दुर्ग ना बस्तर ना सरगुजा कही भी कोई सुरक्षित नहीं है।

लालजीत राठिया ने कहा कि राज्य में हत्या,अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं। अनिल भेड़िया ने कहा कि इस तरह का माहौल पूरे राज्य में है। सावित्री मंडावी ने कहा कि अपराध बढ़ने से जनता में नाराज़गी है। कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भाजपा का अमृत काल नागरिकों के लिए विषकाल बन रहा है। द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, आज अपराध का गढ़ के रूप में पहचाना जा रहा है। रामकुमार यादव ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मर्डर का तरीक़ा बदल गया है। गला रेतकर हत्या हो रही है। घर में जलाकर मारा जा रहा है। हर्षिता बघेल ने कहा कि कवर्धा में एसपी कार्यालय के सौ मीटर की दूरी पर एक माँ बेटी को मार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कवर्धा में ही छह हत्या हो गई। भाजपा के अमृतकाल में ये क्या हो रहा है। जब गृहमंत्री के ज़िले में ऐसा भय का माहौल हो तो प्रदेश में उसका व्याप्त होना लाज़मी है। मनेंद्रगढ़ में एक महिला को गोली मारकर मार दिया गया। विधानसभा थाने के क़रीब गोली चल गई। साधु-संतों पर हमला हो रहा है। थाने के भीतर महिला ज़हर पी रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की।

सदन में उठा रेत के अवैध भंडारण का मुद्दा

भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेत के अवैध भंडारण का मामला उठाया। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि जुर्माने की राशि के अलावा पोकलेन मशीन जब्त की जाती है। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सिर्फ़ रुपए वसूली करने भर से विभाग की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। बिलासपुर संभाग में तीन सालों तक मामूली जुर्माना लेकर इतिश्री कर ली जाती थी। मशीन जप्त नहीं की गई। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। सात दिनों में ही पांच चेन माउंटिंग मशीन, हाइवा जप्त किया गया है। रेत के अवैध खनन पर विष्णुदेव साय सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने प्रश्नकाल में राजनांदगांव में मुरूम परिवहन का मामला उठाया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि राजनांदगांव जिले में अवैध मुरूम परिवहन के 70 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर खदानों के लिए अनुमति दी गई है। जमीन चिन्हांकन, भौतिक सत्यापन के बाद अनुमति दी जाती है।

जैजैपुर पावर प्लांट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जैजैपुर में पावर प्लांट स्थापना का मुद्दा उठाया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आश्वस्त किया कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने मोजर वेयर द्वारा तय समय पर प्लांट नहीं खोलने पर सवाल किया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 65 से 70 माह के भीतर प्लांट खोलना था, लेकिन तय समय पर प्लांट नहीं खुल सका। वर्तमान में अधिग्रहित जमीन भूमि बैंक में संरक्षित है। बालेश्वर साहू ने कहा कि किसानों ने अपनी जमीन बेच दी पर प्लांट शुरू नहीं हो सका। आज किसान न वहां खेती कर पा रहे हैं न लोगों को प्लांट में नौकरी ही मिल पा रही है। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी।

सरकारी शराब दुकानों से अवैध बिक्री का मामला प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच कराएगी सरकार

सदन में मंगलवार को देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होगी? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी। अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मामला उठाते कहा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है। मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है। टेंडर के माध्यम से ख़रीदी की जाती है। राजेश मूणत ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई करती रही? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं। इसलिए तीन टेंडर ही आए। राजेश मूणत ने कहा- 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने टेंडर में भाग लिया था। इसके बाद संख्या कम हो गई। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा कि आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं। मूणत ने कहा कि मतलब इसलिए है क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होगी। जिलो को आठ ज़ोन में बाँटकर तीनों डिस्टलरी से सप्लाई की जाती थी। राजेश मूणत ने कहा कि पांच साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है। ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है। क्या पांच साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टलरी को काम दिया गया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया। दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे। राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी। एक वैध और दूसरा अवैध। अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के खिलाफ़ कार्रवाई हुई। सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाये गये, लेकिन कार्रवाई पांच पर ही हुई। क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

संदेशखाली की घटनाओं पर सीएम साय ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी

रायपुर। संदेशखाली में महिलाओं से दुष्कर्म और आदिवासियों की जमीन छिने जाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री साय ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ङ्क पर शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनायें शर्मनाक है। वारदात में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र प्रेषित कर रहा हूं। आशा है ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेंगी।

गार्गी शुक्ला को मिला गोल्ड मेडल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रतिभावान छात्रा गार्गी

शुक्ला ने प्रदेश से बाहर भी अपना धाक जमाया है। रायपुर में ग्रेजुएशन के बाद गार्गी ने आगे की पढ़ाई सेज यूनिवर्सिटी इंदौर (मध्यप्रदेश) में एमएससी बायोटेक्नोलाजी में की। यहां भी उन्होने अपने मुकाम को जारी रखा और सभी विभागों में उच्च स्थान प्राप्त करने पर विगत दिवस आयोजित समारोह में सेज यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल के साथ डिग्री प्रदान किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि सुंदरनगर निवासी व्याख्याता मृत्युंजय शुक्ला की बिटिया गार्गी शुक्ला हायर सेकेंडरी व स्नातक की परीक्षाओं में भी टापर रही हैं। खेलकूद व डिबेट के अलावा और भी गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रही हैं।

मुख्यमंत्री से रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज

यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी भेंट की। प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री साय को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, उपाध्यक्ष श्री संदीप शुक्ला, प्रेस क्लब महासचिव श्री वैभव शिव पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री रमन हलवाई एवं संयुक्त सचिव द्वय सुश्री तृप्ति सोनी, श्री अरविन्द सोनवानी भी उपस्थित थे।

अरुण साव की बड़ी कार्रवाई, लोक निर्माण विभाग के दो अफसर निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य के लिए कटघोरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया है। वहीं कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप संभागीय अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस किलोमीटर लंबाई के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3 कि.मी.) में

कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम और किए गए कार्य का घनत्व कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी एसपी साहू और उप अभियंता राकेश वर्मा को निलंबित किया गया है। मंत्रालय के जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही अमानक कार्य और मार्ग का डामरीकरण कराकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है।

दूसरी ओर चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण में अमानक स्तर का कार्य एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराए जाने पर कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एके वर्मा और कोरबा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरएन दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व भी कम पाया गया है। दोनों अधिकारियों द्वारा कार्य अमानक स्तर का एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है।

अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा, केदार कश्यप ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से की मुलाकात

रायपुर। बीते 3 महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे अपेक्स बैंक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज अपेक्स बैंक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने 3 महीने से लंबित नियुक्ति को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से उनके निवास स्थान पर मुलाक़ात की, जिसपर मंत्री केदार कश्यप ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे आज ही सेक्रेटी और रजिस्ट्रार से मिलकर नियुक्ति के लिए फैसला करेंगे।

मंत्री केदार कश्यप से नियुक्ति का आश्वासन मिलने के बाद अपेक्स बैंक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में खुशी की लहार है। अपेक्स बैंक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक वह इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और रजिस्ट्रार को नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंप चुके थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से नियुक्ति का आश्वासन मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही नियुक्ति के लिए आदेश जारी होगा।

गौरतलब है कि बीते साल तत्कालीन भूपेश

बघेल सरकार में अपेक्स सहकारी बैंक में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके तहत 407 पदों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था। इनमें प्रबंधक से लेकर, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और कार्यालय सहायक के पद शामिल थे। परीक्षा में बाद विधिवत परिणामों का ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी हैं। इसी कड़ी में अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपने पालकों के साथ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के निवास पहुंचे थे।

बिलासपुर के अपराध जगत में दहशत का माहौल

■ तेज़ तर्रार पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने ऐक्टिवेट किया वृहद् एंटी-क्राइम अभियान

बिलासपुर। बिलासपुर के अपराध जगत में दहशत का माहौल है। अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस कि नीति को फलीभूत करने बिलासपुर पुलिस सघन अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) के निर्देशानुसार लगातार 3 दिनों से सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले गुंडा एवं निगरानी बदमाश तथा विगत 1 वर्ष में जेल से रिहा हुए संपत्ति संबंधी अपराधों (चोरी, लूट, डकैती आदि) में संलिप्त आरोपियों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही समंस, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थायी वारंट की चेकिंग हेतु भी अभियान चलाया जा रहा है।

यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(शहर) श्री राजेंद्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्रीमती पूजा कुमार (भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) श्री उमेश कुमार गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक (रक्षित केंद्र) श्रीमती मंजुलता केरकेट्टा, नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) श्री कृष्ण कुमार पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (कोटा) श्री सिद्धार्थ बघेल तथा प्रशिक्षु आईपीएस श्री अजय कुमार के पर्यवेक्षण में चलाया गया।

चेकिंग के दौरान अपने थाना क्षेत्र में निवासरत गुंडा एवं निगरानी बदमाश, पिछले 1 वर्ष में जेल से रिहा हुए संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य उनके निवास स्थान पर जाकर भौतिक रूप से चेक किया गया तथा कुछ को थाने बुला कर चेक किया गया। इसमें आरोपियों के वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर, उनके आजीविका के साधन, उनके निवास आदि में हुए परिवर्तन सहित अन्य जानकारियां एकत्र की गयी।

गुंडा तथा निगरानी बदमाशों के आजीविका के वर्तमान साधनों के बारे में जानकारी ली गयी तथा इन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने हेतु कड़ी चेतावनी दी गयी। अपने निवास स्थान पर अनुपस्थित पाए गए व्यक्तियों की पतासाजी की जाकर उनकी भी गुजर जांच की जा रही है। इसके साथ ही समंस, गिरफ्तारी वारंट तथा स्थायी वारंट की तामीली हेतु भी विशेष अभियान चलाया गया।

छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में विज्ञान की भूमिका पर हुई चर्चा

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और छत्तीसगढ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में आयोजित दो दिवसीय 19 वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय यह सम्मेलन 26 एवं 27 फरवरी तक आयोजित होगा। निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर प्रोफेसर एन. वी.रमणा राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तरक्की कर रहा है। आज हम सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार की चर्चा करेंगे। नई विचारधारा और अनुसंधान को बढ़ावा देंगे और आगे के विषय में कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र मी आगे बढ़ेगी। आज हम इस समारोह को विकसित भारत 2047 के सन्दर्भ में भी देखते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। 2047 की दिशा में हम ऐसे भारत की दिशा में काम कर रहे हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी हो, जो नवाचारों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक उत्थान को प्राप्त करेगा।

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर

प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी भाजपा: अभिषेक सिंह

बालोद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और उससे पहले कार्यालय की शुरुआत भी की जा रही है। बालोद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने लोकसभा चुनाव कार्यालय की शुरुआत की, उनसे पूछा गया कि अभी तो नाम फाइनल नहीं हुए हैं परंतु इस कार्यालय का क्या उद्देश्य, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तो तय हैं कि सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल का निशान चुनाव लडने वाला है, कार्यालय खुल रहे हैं हमारी कार्यशैली भाजपा को अन्य दलों से अलग बनाता है।

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि जहां अन्य दलों की राजनीति व्यक्ति केन्द्रित होती है वहीं भाजपा की राजनीति राष्ट्र केंद्रित होती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भी पलटवार किया है, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा की यदि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर भारती योजना को बंद किया जाएगा, इसको लेकर

अभिषेक सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की राजनीति अलग है हमने देखा है कि हमारी योजनाओं को भी बंद कर देते हैं पर पूरे देश को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि यहां आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नई रणनीति तैयार करने के साथ-साथ पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यकर्ताओं की चुनाव संबंधी बैठक ली जाएगी। पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी नई चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता अभी से चुनावी समर के काम में जुटेगा।

राजनांदगांव में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन

खैरागढ़। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राजनांदगांव सीट के खैरागढ़ में आज लोकसभा चुनाव प्रभारी नारायण चंदेल सांसद और संतोष पाण्डेय की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चुनाव कार्यालय स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने जिला भाजपा कार्यालय में बनाया गया है। उद्घाटन के मौके पर चुनाव प्रभारी नारायण चंदेल सांसद संतोष पाण्डे प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव समेत तमाम जिला भाजपा के नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा प्रभारी नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को जीत का नुस्खा बताया और उसमें जोश भरने का प्रयास किया। राजनांदगांव लोकसभा में कुल आठ विधानसभा सीटें आती है पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में यहां केवल तीन ही सीटें आई हैं बाकी की पांच सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में राजनांदगांव सीट पर भाजपा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

हाईकोर्ट से लखमा को बड़ी राहत, सुकमा का बंगला खाली करने के आदेश पर रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद राज्य शासन की ओर से सुकमा में कवासी लखमा को आवंटित बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री लखमा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुकमा एसपी बंगला के पास आवास आवंटित किया गया था, जिसे खाली करने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उन्हें दूसरी जगह आवास आवंटित करने का आदेश जारी किया गया है। कोंटा विधायक कवासी लखमा ने एडवोकेट अविनाश के मिश्रा के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी।

कोंटा विधायक कवासी लखमा ने बिलासपुर हाईकोर्ट को बताया कि नक्सलियों के हिट लिस्ट में होने की वजह से उन्हें सुकमा एसपी बंगला के पास आवास आवंटित किया गया था। ताकि सुकमा एसपी बंगले के साथ साथ उनके बंगले की सुरक्षा भी कड़ी रहेगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवास आवंटन नियम प्रस्तुत करने को कहा था।

जिसके बाद आज मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने के आदेश पर स्टे दिया है।

बस्तर के कोंटा विधानसभा से पूर्व मंत्री कवासी लखमा छह बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसी वजह से नक्सली उन्हें अपनी हिट लिस्ट में रखे हैं। कवासी लखमा पर नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने जेट प्लस सुरक्षा दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुकमा एसपी बंगला से लगा हुआ आवास आवंटित किया गया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उन्हें दूसरी जगह आवास आवंटित करने का आदेश जारी किया गया। इस मकान को मंत्री केदार कश्यप भी आवंटित कराना चाह रहे हैं। प्रशासन की ओर से मंत्री केदार कश्यप के नाम पर उस आवास का आवंटन भी कर दिया गया है। इसी आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।

विपक्ष के पास दिख रहा विकल्पों का अभाव

अभय कुमार दुबे

ऐसा लगता है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ किसी बहुत बड़ी और प्रबल एंटीइनकम्बेंसी की उम्मीद में है। लेकिन क्या ऐसी कोई सरकार विरोधी आंधी चल रही है? मेरा ख्याल है कि विपक्ष के प्रति खासी हमदर्दी रखने वाला कोई समीक्षक भी सत्ता-परिवर्तन कर सकने वाली किसी आंधी को नहीं देख पा रहा है। दस साल तक चलने वाली सरकार के विरोध में कुछ न कुछ नाराजगियां होती ही हैं, लेकिन वे अपने आप में चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं देतीं। सत्ता विरोधी भावना की अनुपस्थिति में विपक्षी उम्मीदवार केवल स्थानीय जातिगत और समुदायगत समीकरणों के आसरे ही रहेंगे। हो सकता है कि कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में उन्हें इस आधार पर कामयाबी मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वह अपवादस्वरूप ही होगा। इस परिस्थिति में मतदाता केवल एक ही पार्टी की सरकार बनते हुए देख पा रहे हैं। जमी हुई सरकार उखाड़ने के लिए किसी वैकल्पिक संरचना को उनके विचारार्थ पेश ही नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार हर मंच से दावा कर रहे हैं कि मई के महीने में होने वाले लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को 370 सीटें मिलेंगी, और एनडीए 400 के आंकड़ें छुएगा। अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए इस तरह की बातें ठीक हैं, लेकिन यह एक तथ्य है कि जब तक भाजपा दक्षिण भारत में जीत हासिल करने लायक समर्थन आधार तैयार नहीं करती, तब तक वह इस तरह का नतीजा हासिल नहीं कर सकती। इससे पहले तो भाजपा को 272 सीटें लाने की गारंटी करनी होगी। पिछली बार उसने कर्नाटक (25), तेलंगाना (4), पश्चिम बंगाल (18), बिहार (17), झारखंड (11) और महाराष्ट्र (23) को मिला कर 98 सीटें जीती थीं। इन सीटों को दोबारा जीतना आसान साबित नहीं होगा। इन राज्यों में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भाजपा की महायुति से आगे है। बिहार में महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। झारखंड में सोरेन सरकार गिराने के चक्कर में भाजपा मात खा चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी 2019 के मुकाबले ज्यादा सतर्क और तैयार हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भाजपा की राह में बहुत मुश्किलें पेश करने वाली है। यह जरूर है कि इस सबके बावजूद भाजपा विपक्ष से बेहतर स्थिति में है। आखिरकार लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन विपक्ष की एकता अपने मुकाम तक पहुंचती दिखने लगी है। पिछले दो लोकसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो इस बार यह एक नई बात होगी। भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकता का सूचकांक 2014 और 2019 में शून्य था। इस बार वह कम से कम शून्य नहीं बल्कि उससे कुछ बेहतर होगा। प्रश्न यह है कि इस विपक्षी एकता की संरचना और राजनीतिक मर्म की समझ किस तरह बनानी चाहिए? क्या विपक्ष उस आश्वासन पर खरा उतर रहा है जो उसने करीब साल-सवा साल पहले देश की जनता को दिया था? राहुल गांधी अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा करते हुए बार-बार कहते थे कि हम विपक्ष के साथ मिल कर भाजपा को हराएंगे। नीतीश कुमार का कहना था कि उनकी दिलचस्पी तो केवल विपक्ष की एकता में है। मेरा आकलन यह है कि गठबंधन तो हुआ है, और बचा-खुचा भी हो जाएगा। लेकिन यह आधा-अधूरा और खींचतान कर किया गया है। इसमें मुद्दों को आपस में गूंथ कर भाजपा द्वारा बनाई जा रही हवा के मुकाबले किसी समांतर हवा को बनाने की कोशिश तक नहीं की गई है। विपक्ष ने सिर्फ अंकगणित तैयार किया है। रसायनशास्त्र की तरफ उसकी निगाहें हैं ही नहीं। वह माहौल तैयार ही नहीं किया गया है जिसके जरिये सत्ता-परिवर्तन की भावना मतदाताओं के बीच फैलती। इस लिहाज से यह पैरों के बल पर नहीं, बल्कि सिर के बल खड़ा गठजोड़ है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव का पर्चा भरने के बाद मतदाताओं के पास महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, मोदी-अदानी संबंध, भारत-चीन सीमा विवाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों के साथ जाएंगे जरूर, लेकिन उनके पास देने के लिए कोई वैकल्पिक संदेश नहीं होगा। वे जनता को यह नहीं बता पाएंगे कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो वे किस तरह नौकरियों और रोजगार का बंदोबस्त करेंगे।

गठबंधन में चतुर कौन, केजरीवाल या कांग्रेस?

अजय सेतिया

आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविन्द केजरीवाल से हाल ही में जब पूछा गया कि आप बाकी जगह तो कांग्रेस से चुनावी गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि यह भाजपा और अकाली दल को हराने की रणनीति है। उनके इस बयान के दो दिन बाद जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में सीट शेयरिंग का एलान हो गया, तो पंजाब के बारे में न कांग्रेस ने कुछ बोला है, न आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल के गठबंधन नहीं करने का एक बड़ा कारण यह है कि वह पंजाब सरकार की मुफ्त वाली स्कीमों और किसान आन्दोलन से फायदा होते देख रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन करके वह उस फायदे को बांटना नहीं चाहते। केजरीवाल यह भी मान कर चल रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने से अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो जाएगा, जिससे इंडी गठबंधन के दोनों दल नुकसान में रहेंगे। वैसे भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस एकमत से आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रही है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन होने से आम आदमी पार्टी की पंजाब में जड़ें जम जाएगी और पंजाब में कांग्रेस की हालत यूपी और दक्षिण भारतीय राज्यों जैसी हो जाएगी, जहां वह प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत में भी नहीं रहेगी। इसलिए दोनों पार्टियों में यह धारणा बन रही है कि अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अकेले ही लड़ना चाहिए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि पंजाब में इंडी एलायंस के दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी में अभी तक की धारणा यह बन रही है कि पांचकोणीय मुकाबले में उसे फायदा होगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल तो मैदान में हैं ही। बसपा का अकाली दल से गठबंधन टूट गया है, और वह भी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी का यह पहला लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव विधानसभाओं की तरह नहीं होते, यह केजरीवाल खुद दिल्ली में दो बार देख चुके हैं। 2014 और 2019 में दोनों बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह हारी। 2015 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले दिल्ली में उसका वोट 15 प्रतिशत घट गया था।

2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 33.1 प्रतिशत वोट मिला, जबकि 2019 के चुनाव में सिर्फ 18 प्रतिशत वोट मिले। इसी तरह 2022 में पंजाब विधानसभा में रिकार्ड तोड़ विजय के बाद आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से खाली की गई लोकसभा सीट ही हार गई थी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हुए समझौते के मुताबिक़ कांग्रेस तीन और आम आदमी पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस पांच सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि आम आदमी पार्टी उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिल्ली की सीट पर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन वहां भी 2014 के मुकाबले उसके 9 प्रतिशत वोट घट गए थे। जबकि भाजपा के रमेश विधूड़ी के वोट 11 प्रतिशत बढ़ गए थे। समझौते में आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के अलावा नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीटें रखी हैं।

नई दिल्ली सीट पर पिछली बार कांग्रेस के अजय माकन दूसरे नंबर पर थे। वह आम आदमी पार्टी से गठबंधन के घोर विरोधी थे। तो उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा टिकट देकर कांग्रेस ने चुप करवा दिया। लेकिन क्या वह आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में जीतने देंगे। और क्या उत्तर पूर्वी सीट से संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी को जीतने देंगे, जहां पिछली बार उनकी मां शीला दीक्षित हारी थी। सच यह है कि कांग्रेस ने इस बार केजरीवाल को आईना दिखाने का मंसूबा बना कर गठजोड़ किया है। इन सभी सीटों पर 2019 में उसका वोट 15 से 21 प्रतिशत तक घटा था। कांग्रेस ने जो तीन सीटें ली हैं, वे मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। केजरीवाल ने खुद हिन्दू बहुल सीटें लेकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। हिन्दू बहुल सीटों पर उनकी दाल बिलकुल नहीं गलने वाली। दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी गलतफहमी में है। शराब घोटाले के बाद यह पहला चुनाव होगा। सिसोदिया का जेल में एक साल पूरा हो चुका है, जिससे दिल्ली की जनता में धारणा बन गई है कि घोटाला न हुआ होता, तो उन्हें जमानत मिल गई होती।

गुजरात में भी कांग्रेस की रणनीति आम आम आदमी पार्टी से बदला लेने की है। भरूच और भावनगर सीट पर कांग्रेस का आसानी से मान जाना, कई तरह के शक पैदा करता है। भरूच अहमद पटेल का घर है। अहमद पटेल 1977 से 1984 तक लगातार तीन बार भरूच से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1989 में वह हार गए, तो उसके बाद से यह सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। दस बार से लगातार कांग्रेस हार रही थी। पिछली छह बार से भाजपा के मनसुख भाई वसावा वहां से सांसद हैं। लेकिन अहमद पटेल राजीव गांधी और सोनिया गांधी के इंतना करीब आ गए थे कि 1993 से 2020 तक पांच बार राज्य सभा के सदस्य रहे। 2020 में कोविड से उनका देहांत हो गया।

अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल वहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की विरासत को मानती है। इसलिए कांग्रेस ने जब यह सीट आम आदमी पार्टी को दी, तो शुरू में वह बहुत परेशान हुई। लेकिन 24 घंटे में उन्हें समझा दिया गया कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को यह सीट हारने के लिए दी है, जीतने के लिए नहीं दी। क्योंकि केजरीवाल को यह भ्रम हो गया है कि भरूच लोकसभा क्षेत्र की सात विधानसभा सीटों में से एक सीट जीत कर वह लोकसभा सीट जीत लेंगे। जबकि बाकी छह विधान सभा सीटें भाजपा जीती थी।

इसी तरह भावनगर भी भाजपा की पक्की सीट है, पिछले 35 साल से कांग्रेस वहां नहीं जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा को 63 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 31 प्रतिशत वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 2014 में जरुर आम आदमी पार्टी को 50 हजार से थोड़ा कम वोट मिल गए थे। भावनगर की सातों विधानसभा सीटें भी भाजपा के पास हैं। तो कांग्रेस ने गुजरात में केजरीवाल को दो सीटें देकर बाकी 24 सीटों को उनके कोप से बचा लिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया था, अब उसे गोदी में बिठा कर बदला लिया जाएगा।

इसी तरह हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट भी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में भविष्य खराब करने के लिए दी गई है। पिछली दो बार से वहां भाजपा जीत रही है। पिछ्ला चुनाव तो वहां भाजपा 55 प्रतिशत वोट हासिल कर के जीती थी। कांग्रेस को भाजपा से आधे वोट भी नहीं मिले थे। आम आदमी पार्टी वहां न तीन में है, न तेरह में। कांग्रेस ने हारने वाली ये तीन सीटें केजरीवाल को देकर गोवा और चंडीगढ़ को उनके कोप से बचा लिया है। पिछली बार गोवा की एक सीट और चंडीगढ़ सीट कांग्रेस केजरीवाल के कोप के कारण हारी थी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-17)

गतांक से आगे...

क्षणमात्र में ही वह आकाश एवं पाताल की सैर कर डालती है, क्षण मात्र में ही दिशारूपी कुञ्जों में भ्रमण करने लगती है। यह तृष्णा हृदय कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह तृष्णा ही इस नश्वर जगत् के समस्त दु:खों में दीर्घ काल तक दु:ख देने वाली है, जो अन्त:पुर में निवास करने वालों को भी महान् संकट में डाल देती है। यह तृष्णा एक महामारी- हैजा है। इसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट कर सकता है, जिसने चिन्ता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यदि चिन्ता का थोड़ा भी परित्याग कर दिया जाए, तो अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ी-सी भी चिन्ता मन में शेष रही, तो उससे असीम दु:ख की प्राप्ति होती है।

देह के सदृश तुच्छ, गुणरहित तथा शोक करने योग्य अन्य दूसरा कोई नहीं। इस शरीर रूपी विशाल गृह में अहंकाररूपी गृहस्थ निवास करता है। यह शरीर चाहे दीर्घकाल तक रहे अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाए, उसकी मुझे किञ्चित् मात्र भी चिन्ता नहीं है। जिस शरीर रूपी घर में इन्द्रियरूपी पशु पंक्तिवत् खड़े हैं तथा जिसके प्रांगण में तृष्णा रूपी बँदरी विचरण करती रहती है, जिसमें चित्त-वृत्तिरूप भृत्यों का समावेश है। ऐसा शरीर रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। जिह्वा रूपी बंदरी से पीड़ित हुआ यह मुख रूपी द्वार इतना भयभीत हो गया है कि आरम्भ में ही दन्तरूपी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं।

ऐसा यह शरीररूपी घर मुझे प्रिय नहीं लगता है। हे मुनीश्वर! यह शरीर बाहर एवं अन्दर रक्त एवं मांसादि से संव्याप्त है, तो इस नश्वर शरीर में रमणीयता कहाँ से आई ? यदि किसी ने शरत्कालीन बादलों की विद्युत् में एवं गन्धर्व की नगरी में स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस नश्वर देह की स्थिरता में विश्वास कर सकता है।

क्रमश: ...

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अनन्या मिश्रा

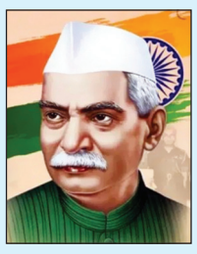

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने आरत की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। बता दें कि वह बिहार के मुख्य नेता थे। वहीं नमक छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद को काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। वहीं भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अहम योगदान था। आज ही के दिन 28 फरवरी 1963 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के महान स्वतंत्रा सेनानी का निधन हुआ था।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई (बिहार) में हुआ था। सादगी पसंद, दयालु एवं निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। उनके पिता फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। महज 12 साल की उम्र में उनका राजवंशी देवी से विवाह हो गया था। बचपन में अपने जन्मस्थान से शुरूआती शिक्षा के दौरान उन्होंने फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए छपरा और फिर पटना गए। जहां पर उन्होंने कानून में मास्टर की डिग्री के साथ डॉक्टरेट भी किया। कानून की पढ़ाई के दौरान वह राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए थे।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं महात्मा गांधी ने उनको अपने सहयोगी के तौर पर चुना था। इसी के साथ गांधी जी ने उन पर साबरमती आश्रम की तर्ज पर सदाकत आश्रम की एक नई प्रयोगशाला का दायित्व सौंपा था। ब्रिटिश प्रशासन ने राजेंद्र प्रसाद को नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डालकर कई तरह की यातनाएं दी थीं।

आपको बता दें कि डॉ राजेंद्र प्रसाद साहित्य-संस्कृति, शिक्षा, इतिहास, धर्म, वेदांत, राजनीति, भाषा आदि विषयों पर वह अपने विचार व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते थे। स्वाभाविक सरलता के कारण उन्होंने कभी भी अपने प्रभाव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन-उच्च विचार के सिद्धांत को अपना कर चलने वाले व्यक्ति थे। वह सभी से काफी नम्रता से बात करते थे। उनकी यही प्रतिभा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी।

देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला। इसके साथ ही डॉ राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रा भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 में वह दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। बता दें कि डॉ राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनें। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए साल 1962 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के तौर पर भारत रत्न से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने अपने राजनैतिक सफर पर विराम लगाते हुए सन्यास ले लिया।

तेजी से अपने आप को क्यों बदल रहा है सऊदी अरब?

संजय तिवारी

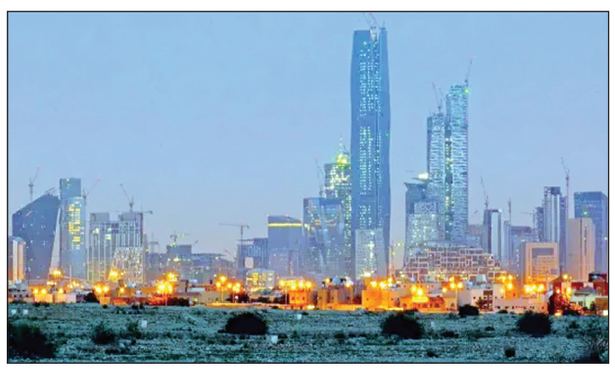

इस महीने की शुरुआत में मलेशिया के क्वालालाम्पुर में मिस एशिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हालांकि विजेता फिलीपीन्स की डेन शेन मैग आबो रहीं लेकिन उनसे अधिक चर्चा में आयीं रूमी अलखातनी। रूमी अलखातनी सऊदी अरब की मॉडल हैं और उनका इस प्रतियोगिता में शामिल होना ही सोशल मीडिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। अरब न्यूज ने भी इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब से पहली बार कोई औरत इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल हुई है। मिस सऊदी अरब रह चुकी रूमी अलग अलग समय में अब ऐसी प्रतियोगिताओं में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने लगी हैं। मलेशिया से लेकर यूरोप तक। वो सऊदी अरब में महिला सौंदर्य, मेधा, प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने के साथ उस मर्दवादी मानसिकता को भी चुनौती दे रही हैं जो अब तक सऊदी अरब की पहचान रहा है। लेकिन यह सब वो अनायास ही नहीं कर रही हैं। इसके लिए सऊदी अरब के उसी मर्दवादी कबीले ने उन्हें आगे बढाया है जो कल तक किसी महिला के बिना महरम के घर से निकलने को भी अपराध मानता था।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में लगातार ऐसे सामाजिक और प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं जो सऊदी अरब की कट्टर इस्लामिक मानसिकता पर ही प्रहार करते हैं। लड़कियों को सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होने देना बिना इन सुधारों के संभव नहीं था। वर्तमान सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल्ल अजीज इब्न सऊद के पोते मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद बीते चार पांच सालों से सऊदी अरब में ऐसे सामाजिक सुधार को बढावा दे रहे हैं ताकि उनका देश बदलती दुनिया के साथ कदमताल कर सके।

इसमें सबसे बुनियादी सुधार महिलाओं को लेकर अब तक रहा सऊदी अरब का नजरिया है। इसके दो कारण हैं। पहला इस्लाम और दूसरा वह नज्द कबीला जिससे इब्न सऊद ताल्लुक रखते थे। सऊदी अरब का नज्द कबीला औरतों को लेकर बहुत कट्टर समझा जाता है। आज दुनियाभर में इस्लाम के नाम महिलाओं को जो काला बुर्का पहनाया जाता है वह इस्लाम का नहीं नज्द कबीले की निशानी है। अरब भूमि के अलग अलग हिस्सों और कबीलों में अलग अलग रंग के अबया और बुर्कों का चलन है। लेकिन जब किंग अब्दुल्ला ने सऊदी अरब का पुनर्गठन करके अपने आपको किंग घोषित किया तब इस्लाम के साथ साथ नज्द कबीले की रिवायतें भी सऊदी अरब की पहचान बन गयीं।

इसलिए उसी आले सऊद परिवार की तीसरी पीढी मोहम्मद बिन सलमान अगर महिलाओं को लेकर सऊदी अरब का नजरिया बदल रहे हैं तो वो इस्लाम से अधिक अपनी उस कबीलाई मानसिकता का त्याग कर रहे हैं जो उनकी पहचान रही है। इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए जरूर कहा गया है लेकिन एक खास रंग का बुर्का पहनने या सिर पर हिजाब बांधने से ही उसे पर्दा कहा जाएगा, ऐसा इस्लाम में कहीं कोई जिक्र नहीं है। काला बुर्का अगर अरब के नज्द कबीले के कारण मुस्लिम महिलाओं की पहचान बना तो हिजाब ईरान में इस्लामिक राज्य स्थापित करनेवाले अयातोल्ला खोमैनी के कारण चलन में आया।

2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) को उनके पिता किंग सलमान द्वारा अपना उत्तराधिकारी और क्राउन प्रिंस घोषित किया गया तब से ही एमबीएस ने यह बताने का प्रयास किया कि सऊदी का समाज कट्टर नहीं है। आज सऊदी अरब में जो इस्लामिक कट्टरता दिख रही है वह अयातोल्ला खोमैनी की वजह से है। हालांकि सुनने में यह बात उतनी सीधी नहीं लगती लेकिन ऐसा कहने के पीछे एमबीएस का अपना संकेत होता था। वह यह कि हम इस्लाम से अधिक अपने कबीलाई कल्चर में भरोसा करते हैं। इसलिए इस्लामिक कट्टरता का आरोप उन पर लगाना गलत होगा।

बहरहाल, बीते पांच सालों में एमबीएस ने सऊदी अरब के सामने एक नयी पहचान का प्रस्ताव किया है। वह पहचान अतीत के अरब की नहीं बल्कि भविष्य के यूरोप की है। इसलिए केवल सऊदी अरब की महिला विश्व की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में ही हिस्सा नहीं ले रही है बल्कि सौंदर्य सामग्री के व्यापार को बढावा देने के लिए ब्यूटीवर्ल्ड सऊदी अरबिया का आयोजन करने लगा है। इस साल फरवरी महीने में यह आयोजन हो चुका है और अगले साल अप्रैल में आयोजन की घोषणा की जा चुकी है।

सिर्फ महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देने, उन्हें सौंदर्य प्रतियोगिता में बिना हिजाब के शामिल होने या फिर अकेले घर से बाहर आने जाने की अनुमति ही वो सामाजिक सुधार नहीं है, जो सऊदी अरब में हो रहे हैं। सच्चे इस्लाम का प्रचार करने का दावा करनेवाली तब्लीगी जमात पर सऊदी अरब प्रतिबंध लगा चुका है। इन सामाजिक और धार्मिक सुधारों को जारी रखते हुए मस्जिदों में बच्चों के साथ प्रवेश, ऊंची आवाज वाले लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों में होनेवालों खुतबों को भी नियंत्रित कर दिया है।

अब सऊदी अरब में रमजान के महीने में मस्जिदों में इफ्तार का आयोजन नहीं होगा। मस्जिदों के इमामों द्वारा इसी महीने में सबसे अधिक जकात इकट्ठा किया जाता है। सऊदी अरब ने इस पर भी रोक लगा दी है। इमामों को सऊदी के इस्लामिक मंत्रालय द्वारा सलाह दी गयी है कि रमजान के दौरान वो लंबी तकरीर न दें और सिर्फ लाभकारी बातें ही मुसलमानों को बतायें जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल में ही कहा है कि कट्टरता को खत्म करने के लिए वो लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हमें आज ही उसको खत्म करने के लिए काम करना होगा।

एक ओर सऊदी अरब इस्लामिक और कबीलाई कट्टरता को सीमित कर रहा है तो दूसरी ओर सऊदी अरब में पर्यटन को बढावा देने के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी कर रहा है। यूएई को देखकर सऊदी अरब के शासकों को समझ में आने लगा है कि अपने मुताबिक दुनिया को बदलने की बजाय दुनिया के मुताबिक अपने आप को बदलने में ही समझदारी है। इसलिए रियाद में संसार का द मुकाब प्रोजेक्ट हो या सबसे लंबी दीवारों के द नियोम नामक शहर बसाने का प्रोजेक्ट। सऊदी अरब दुनिया के गैर मुस्लिमों के लिए अपने दरवाजे खोलना चाहता है। वह चाहता है कि तेल और गैस की अर्थव्यवस्था खत्म होते होते वह दुनिया के लिए एक टूरिस्ट हब बनकर उभरे जैसे आज दुबई बन चुका है।

इसलिए अपने प्रचार अभियान में वह मक्का मदीना की बजाय %आभा% को प्रचारित कर रहा है जो सऊदी अरब का एकमात्र सर्वाधिक हरा भरा राज्य है। यह कहते हुए कि सऊदी अरब का अर्थ रेगिस्तान ही नहीं होता। एमबीएस समझते हैं कि अगर सऊदी अरब की ओर गैर मुस्लिमों को आकर्षित करना है तो उसे अपनी इस्लामिक कट्टरता वाली छवि खत्म करना होगा। इसलिए वह अपने आप को तेजी से बदल रहा है। भले ही दुनिया के कुछ हिस्से में रहनेवाले मुसलमानों को यह पसंद आये या न आये, सऊदी अरब बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है।

आज का इतिहास

1950 द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना।
1972 जापानी पुलिस ने अर्धसैनिक समूह युनाइटेड रेड आर्मी के सदस्यों द्वारा दस दिन की घेराबंदी को समाप्त करने के लिए, करुनिजावा, नागानोप्रेक्नर के पास एक पहाड़ लॉज पर हमला किया।
1972 अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पीपुल्स रिपब्लिक चीन यात्रा दोनों देशों के साथ संपन्न हुई, जिसमें शंघाईकोमुनिके जारी किया गया, जो पूर्ण-सामान्य संबंधों की दिशा में काम करने का वचन देता है।
1974 पाकिस्तान में 6.3 तीव्रता के भूकंप में 5200 मरे गए।
1982 एडोब सिस्टम की स्थापना की गई।
1985 द ट्रॉबल्स-द प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड के कोरी स्क्वायर, रॉयल में एक यूलस्टर कांस्टेबुलरी स्टेशन पर नौ हमले की शुरुआत करते हुए हमला किया।
1986 स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या स्टॉकहोम में एक अकेला बंदूकधारी ने की थी, जब वह अपनी पत्नी लिस्बेट पाल्मे के साथ फिल्म थियेटर से घर लौट रहे थे।
1991 फ़ार्स की खाड़ी के 40 दिवसीय युद्ध में अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश सीनियर ने संघर्ष विराम की घोषणा की।
1995 डेनवर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल गया।
1996 38 वां ग्रैमी अवार्ड्स आयोजित किया गया था। जैगड लिटिल पिइल और अलनीस मौइसेट विजेता थे।
1997 धूम्रपान करने वालों को यह साबित करना होगा कि वे 18 वर्ष से ऊपर हैं, तभी उन्हें अमेरिका में सिगरेट खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
1997 जो कुछ भी उत्तर-आधुनिक तख्तापलट के रूप में देखा गया है, तुर्की के सैन्य नेतृत्व ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें अंतत: तुर्की के प्रधानमंत्री नेकमेक्टिन एर्बाकन की सेवानिवृत्ति की संभावना व्यक्त की गई।
1998 वैंकूवर कैनक्स मेस्सीज 1600 अंक पाने वाले 9 वें NHLen बन गए।
2001 इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर के सेल्बी के पास ग्रेट हेक में एक हाई-स्पीड ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें दस यात्रियों की मौत हो गई और 82 अन्य घायल हो गए।
2003 संयुक्त राष्ट्र के मुख्य हथियार निरीक्षक हंस ब्लिक ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इराक के पास सामूहिक विनाश के कोई हथियार थे।
2003 अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया।

क्या लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन भाजपा को चुनौती दे पायेगा?

ललित गर्ग

अंधेरों एवं निराशा के गर्त में जा चुके एवं लगभग बिखर चुके इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरों ने जहां उसमें नये उत्साह का संचार किया है वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिये चिन्ता के कारण उत्पन्न किये हैं। पहले उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीट बंटवारे पर बनी सहमति ने टूट की कगार पर पहुंचे इंडिया गठबंधन में वर्ष 2024 के आम चुनावों को लेकर संभावनाभरी तस्वीर को प्रस्तुत किया है। अब ये चुनाव दिलचस्प होने के साथ कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर वाले होंगे। इन नये बन रहे चुनावी समीकरणों के बावजूद भाजपा के लिये अभी कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। भले ही इंडिया गठबंधन डींगे हांके कि वह भाजपा एवं उसके गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति आ गयी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का जब गठबंधन बना तभी यह आशंका की गयी कि यह कितनी दूर चल पायेगा, टिक पायेगा भी या नहीं? कुछ हालात तो ऐसे भी बने कि इसके तार-तार होने की संभावनाएं बलवती हुईं। भले ही अब कुछ सीटों पर दलों के बीच सहमति बनी हो लेकिन अभी कई महीने निकल जाने के बाद भी विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम घोषित नहीं हो पाना अनेक सन्देहों एवं अटकलों का कारण बना हुआ है।

सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार दल-टूटन व गठबंधन हो रहे हैं इससे सबके मन में अकल्पनीय सम्भावनाओं की सिहरन उठती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र में टकराव होता है। विचार फर्क भी होता है। मन-मुटाव भी होता है पर मर्यादापूर्वक। लेकिन अब इस आधार को ताक पर रख दिया गया है। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं होते।

अवसरवादिता दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। यह भी बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। राजनीति नफा-नुकसान का खेल बन रहा है, मूल्य बिखर रहे हैं। चारों ओर सत्ता की भूख बिखरी है। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले तो कांग्रेस ने ही पिछले साल दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी बातचीत को ठंडे बस्ते में डाले रखा। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं में न तो पहले जैसा जोश दिखा और न वैसी राजनीतिक जिजीविषा महसूस हुई। फिर गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़-चढ़कर काम करने वाले नीतीश कुमार ही उसे छोड़ गए। यूपी में रालोद के जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का हाथ थामते-थामते एनडीए में शामिल हो गए।

इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस ने अनेक झटके झेले। छोटे-बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम खास तौर पर चर्चित रहा। इसे चाहे इन नेताओं का व्यक्तिगत अवसरवाद कहें या भाजपा और एनडीए नेतृत्व की सक्रियता एवं राजनीतिक कौशल इतना तय है कि इन नेताओं को कांग्रेस का भविष्य खास अच्छा नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी जैसे दल अपनी साख बचाने एवं सत्ता के करीब बने रहने के लिये सीटों के बंटवारे पर सहमत हुए हैं, उसमें कांग्रेस का घुटने टेकना भी उसकी टूटती सांसों को बचाने की जद्दोजहद ही कहीं जायेगी। कांग्रेस एवं अन्य दलों के बीच सहमति के स्वर उभरने से आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा मुकाबला दिख सकता है। लेकिन अहम सवाल तो यही है कि क्या गठबंधन की गाड़ी आगे और हिचकोले नहीं खाएगी? क्या यह दावा पूरी दृढ़ता से किया जा सकता है?

अरविन्द ने कांग्रेस से सीटों पर सहमति बनाकर पलटूराम ही बने हैं। जी-भरकर एक-दूसरे को कोसने वाले जब हाथ मिलाएं तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। देखा जाये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होना मूल्यहीनता एवं सिद्धान्तहीनता की चरम पराकाष्ठा है क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ कर और आंदोलन खड़ा करके ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया और अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के चमत्कारिक प्रदर्शन के चलते ही गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुँचाया और हरियाणा में भी अपने संगठन का आधार बढ़ाया। ताजा कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी की सहमति से कांग्रेस को ही नुकसान होना है। केजरीवाल की बजाय ममता बनर्जी ने अलग छाप छोड़ी है। उसने बंगाल में कांग्रेस के लिए उनकी मौजूदा दो लोकसभा सीटों को ही छोड़ने की बात कह कर कांग्रेस के अधिक सीटों पर दावा करने के कारण स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन को धराशायी किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा, असम और गोवा में भी स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, जिससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में निराशा ही हाथ लगेगी।

इंडिया गठबंधन के नये बन रहे सकारात्मक परिदृश्यों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सेहत पर कोई असर न झलकना उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परिचायक है। 2024 के चुनावों में भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय करने के मोदी के लक्ष्य के सामने अभी भी कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है। इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाजपा एवं मोदी अपनी सीटें कहां से बढ़ा सकेंगे, इसके लिये भाजपा दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। पहली है, दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाना। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भाजपा पहले ही उत्तर-पश्चिम के कई राज्यों में चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरी रणनीति है पुराने सहयोगियों को एनडीए में वापस लाने और नए सहयोगियों को जोड़ने की, जिसमें वह अब तक काफी हद तक सफल भी रही है। जदयू एनडीए के साथ फिर से आ गई है, रालोद भी एनडीए में लौट आई है, पंजाब में अकाली दल को वापस लाने के प्रयास जारी हैं और तेदेपा के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। कुछ और पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं। लेकिन एनडीए के विस्तार भर से भाजपा को 2024 में 370 सीटें नहीं मिलने वालीं। अभी उसे काफी जोड़-तोड़ करने होंगे।

गौरतलब है कि अमित शाह ने तमिलनाडु की कमान संभाल ली है और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के. अन्नामलै को काम करने की खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु का दौरा किया है, जिसे दक्षिण में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। केन्द्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सक्रिय किया गया है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राम मंदिर का उत्साह निश्चित रूप से उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के राज्यों में अधिक है, लेकिन दक्षिण भी भाजपा को कुछ चुनावी लाभ दे सकता है। याद रहे कि भाजपा ने पहले ही दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए मतदाता-पहुंच कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तेलंगाना और केरल आदि दक्षिण के राज्यों पर भाजपा विशेष बल दे रहा है, वहां भी इस बार अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। भाजपा के राजनीतिक समीकरणों एवं रणनीतियों के चलते स्वतंत्र भारत का सबसे दिलचस्प चुनाव में अपने तय लक्ष्यों के अनुरूप ऐतिहासिक जीत को हासिल कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं है।

फिर से एकजुट हो रहा इंडिया गठबंधन!

राजकुमार सिंह

लोकसभा चुनाव का बिगुल तो मार्च में बजेगा, पर बिसात बिछनी शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के अलगाव से बिखराव के कगार पर दिख रहे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की गाड़ी भी पटरी पर वापस लौट रही है। सपा और आप के साथ कांग्रेस का सीट बंटवारा हो चुका है तो तृणमूल कांग्रेस से बातचीत निर्णायक दौर में होने के संकेत हैं। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी और शरद पवार में संवाद से सबकुछ तय हो जाने के दावे हैं। नीतीश के बाद जयंत चौधरी के झटके से लगा था कि 'इंडिया' इतिहास की बात है, लेकिन 21 फरवरी को सपा और कांग्रेस के बीच अचानक हुए सीट बंटवारे के बाद समीकरण तेजी से बदले हैं। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस 17 सीटों पर मान ही गई, जिस सपा को विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक भी सीट देने लायक नहीं समझा था, उसे अब खजुराहो लोकसभा सीट दे दी गई। अब आप और कांग्रेस में दिल्ली ही नहीं, बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सीट बंटवारा हो गया है। अगर ममता बनर्जी असम और मेघालय में सीट मिलने पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दो सीटों से ज्यादा देने पर मान जाती हैं, तो वहां भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाम मोर्चा की भूमिका पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। तय है कि मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधनों- एनडीए और 'इंडिया' के बीच होगा। चुनाव एकतरफा भी नहीं होगा, लेकिन पिछले दिनों 'इंडिया' के अंतर्कलह से जो नकारात्मक संदेश गए हैं, उनसे उबरना आसान नहीं। चुनावी राजनीति अंकगणित नहीं होती, पर सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.4 प्रतिशत वोट ही मिले थे। पूरे एनडीए का वोट प्रतिशत भी 45 से ऊपर नहीं गया यानी 55 प्रतिशत वोट गैर एनडीए दलों को मिले। पर क्या पिछले दस साल में-खासकर 'इंडिया' बनने के बाद विपक्ष वैसी विश्वसनीयता बना पाया है कि अतीत के अनुभवों को नजरअंदाज कर मतदाता उस पर दांव लगा सकें? विश्वसनीयता उन मुद्दों पर जनमत जगाने और जनादेश हासिल करने के लिए भी अहम् है, जिन पर 'इंडिया' चुनाव में मोदी सरकार को घेरना चाहेगा। बेशक एनडीए में 'इंडिया' से ज्यादा घटक दल हैं। सीट बंटवारा आसान नहीं होगा, लेकिन वैसी अराजकता वहां नहीं दिखती, जैसी नवंबर में हुए पांच राज्यों के चुनावों के बाद 'इंडिया' में नजर आई। लोकसभा चुनाव की घोषणा दूर नहीं है, पर 'इंडिया' पीएम फेस तो दूर, संयोजक और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तक तय नहीं कर पाया है जबकि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी के रूप में जांचा-परखा, अनुभवी और सर्व स्वीकार्य नेतृत्व भी है।

चुनाव में काले धन का खेल फिर भी चलेगा

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को रद्द करने की सराहना क्यों की। हां, यह बात जरूर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अपारदर्शी थे। पता नहीं चलता था कि किसने किसे पैसा दिया। लेकिन, बात यह भी है कि ऐसी किसी स्कीम के बिना चुनावों में वाइट मनी घट जाएगी और पहले की तरह ही ब्लैक मनी का बोलबाला हो जाएगा। कई आलोचक चुनावों में पैसों की भूमिका पर रोना रोते हैं। लेकिन, लोकतांत्रिक राजनीति महंगी है। लोकतंत्र में चुनाव और पैसों के बीच का संबंध बहुत गहरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों का कहना है कि भले ही पैसा राजनीति से जुड़ा हो, लेकिन कौन किसे फंडिंग कर रहा है, इस पर पारदर्शिता की जरूरत है। अफसोस कि इस तरह की पारदर्शिता लाने की कोशिश में फंडिंग पर्दे के पीछे से हो सकती है। ऐसे में पारदर्शिता पहले से और कम हो जाएगी।

फंडिंग में इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रहा। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, 2017-18 और 2022-23 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों ने कुल 11,989 करोड़ रुपये जुटाए। मतलब कि हर साल करीब दो हजार करोड़ रुपये। जिन लोगों को राजनीति की हकीकत पता है, वे आपको बताएंगे कि चुनावों पर असल में इससे कहीं अधिक खर्च किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये कुछ वाइट मनी मिल रही है, लेकिन ब्लैक मनी की फंडिंग भी बनी हुई है।

एडीआर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा की हिस्सेदारी 54.8 फीसदी थी। कुछ आलोचकों के मुताबिक, भाजपा को मिली फंडिंग अनुचित रूप से अधिक है। सच पूछिए तो यह बहुत कम है। कारोबारी इसलिए चंदा देते हैं ताकि नेताओं की ओर से उनके कामकाज में कोई बाधा खड़ी न की जाए। इस पहलू से देखें तो रूलिंग पार्टी को तो और भी चंदा मिलना चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया उसमें भाजपा की हिस्सेदारी 54

फीसदी ही रही। भारत में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में हार सकती हैं, लेकिन दलबदलुओं को खरीद कर या सत्तारूढ़ विधायकों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने के लिए राजी करके सत्ता में आ सकती हैं। 2018 में कर्नाटक, 2020 में मध्य प्रदेश और 2023 में महाराष्ट्र में जो हुआ वह इस बात का उदाहरण है। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि इस काम के लिए बहुत पैसा बहाया गया। जाहिर है कि यह पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, बल्कि दूसरे रास्तों से आता है।

उद्योगपति और राजनेता नवीन जिंदल ने एक बार कहा था कि व्यापारियों से नेता जो धन लेते थे, उसका बमुश्किल एक प्रतिशत ही चुनाव पर खर्च किया जाता था। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल फंडिंग उद्योगपतियों द्वारा राजनेताओं की खरीद-फरोख्त नहीं है बल्कि राजनेताओं द्वारा पैसों के बदले सुरक्षा देने का एक अभियान है। भले ही नवीन जिंदल ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़ा पेश किया हो, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि चुनावी खर्च कुल राजनीतिक खर्च का एक अंश मात्र है। पैसों और राजनीति के बीच जो संबंध है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बहुत मामूली है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लोगों को किसी भी मुद्दे पर प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। इसी वजह से किसी व्यक्ति द्वारा किसी राजनेता या पार्टी को दिए जाने वाले डोनेशन पर कानूनी सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन लोग अपने पसंदीदा नेता या पार्टी से जुड़े मुद्दों के प्रचार अभियान पर खुलकर खर्च कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन किए बिना आप राजनीति से पैसों को अलग नहीं कर सकते। यह लोकतंत्र को दोषपूर्ण बनाता है, फिर भी दूसरे सिस्टम से बेहतर है। इसी वजह से राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सुझाए गए सुधार ब्लैक मनी के आगे फेल हो जाएंगे। यह दुख की बात है, लेकिन सच है।

किस बात का डर। पैसों से चुनाव नहीं जीता जाता। रूलिंग पार्टी विपक्षी दलों की तुलना में कॉरपोरेशन और धनपतियों से ज्यादा पैसा निकाल सकती है। बावजूद इसके, भारी खर्च करने के बाद भी सत्ताधारी दल अक्सर चुनाव हार जाते हैं। फिर भी पार्टियां लाखों रुपये खर्च करती हैं, क्योंकि कई चुनाव एक फीसदी या उससे भी कम वोट से जीते जाते हैं। कुल मिलाकर, खर्च किए गए धन और हासिल की गई सीटों के बीच कोई संबंध नहीं है। आलोचकों का यह डर आधारहीन है कि उद्योगपति अपने धन के दम पर राजनेताओं को खरीद सकते हैं। नवीन जिंदल की टिप्पणी से यह बात जाहिर हो जाती है।

साल 1977 में इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटना पड़ा था, क्योंकि वोटर्स नफरत करते थे इमरजेंसी से। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें तेजतर्रार समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में दिए एक यादगार भाषण में उन्होंने कांग्रेस के आगे झुकने और फंडिंग करने के लिए व्यापारियों की निंदा की थी। इसके तुरंत बाद एक बिजनेसमैन ने जॉर्ज फर्नांडिस को एक गुमनाम और खुला खत लिखा। उसमें फर्नांडिस से पूछा गया कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें उस कांग्रेस से प्यार है, जिसने हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इनकम टैक्स 97.7 फीसदी तक बढ़ा दिया? बेशक हमने शब्दों और नकदी के रूप में उपहार अर्पित किए, लेकिन हम प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री के पद को सम्मान दे रहे थे, उन पदों पर बैठे व्यक्तियों को नहीं। यह बात आज भी सच है।

एक भारत, सदैव भारत

डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे

अभी हाल ही में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश ने कहा कि अगर विभिन्न करों से एकत्रित धनराशि के वितरण के मामले दक्षिण राज्यों के साथ हो रहे अन्याय को ठीक नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नि:संदेह बजट प्रस्तावों की तीखी आलोचना करने में कोई बुराई भी नहीं है, यदि आप देश के सामान्य नागरिक हो या फिर सांसद आपको बजट पर अपनी बेबाक राय रखने का पूरा हक है, परंतु एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस तरह की बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है, कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए अलग देश बनाने की मांग करने लगे क्योंकि उसे बजट प्रस्ताव पसंद नहीं आया। धिक्कार है ऐसे सांसद पर, अपमान है भारतीय संविधान का जिसकी शपथ लेकर चुने गए और संसद में वही शपथ लेकर बैठे तथा अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। देश को सांसद सुरेश से यह पूछने का हक है, कि उन्होंने भारत को बांटने संबंधी बयान क्यों दिया? तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के लोग पहले भी अलग देश की मांग कर चुके है।

आजादी के समय भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली और बड़ी समस्या जो सामने भी वह यह थी कि रियासतों का समान रूप से प्रशासित भारत की अवधारणा में एकीकरण। चूंकि इन रियासतों को 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के दौरान बड़े पैमानें पर अंग्रेजो द्वारा संरक्षण दिया गया था इसलिए वे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को छोड़ने के विचार से सहमत नहीं थें इसलिए रियासतों के एकीकरण का कार्य सरदार पटेल को सौंपा गया और 1947 के भारतीय स्वंत्रता अधिनियम द्वारा रियासतों को

भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया और अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग ।एठएब् व क् राज्यों में विभाजित किया गया तथा रियासतों को पुनर्गठित किया गया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठत आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केन्द्रशासित प्रदेशो में पुनर्गठित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने नवंबर 1956 में पारित राज्य पुर्नगठन आयोग के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केन्द्रशासित प्रदेशो में विभाजित किया, यह पुनर्गठन भाषायी आधार पर हुआ ओर आंध्रप्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया।

देश में 1950 में संविधान लागू हो चुका था और संविधान निर्माता इस बात को भली-भांति जानने थे कि हमने रियासतों को मिलाकर राज्य का निर्माण किया है और इससे संघ की स्थापना की है यह राज्य कभी भी अलग होने की मांग कर सकते है, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान किया गया कि भारत अर्थात इण्डिया राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातें स्पष्ट करती है एक देश का नाम और दूसरा राज पद्धति का प्रकार।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार राज्यो का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्त्व देने के दो कारण हैं पहला यह कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसे कि अमेरिका में है तथा दूसरे राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह इस प्रकार का संघ है जो विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यो में प्रशाषनिक सुविधा के लिए बटां हुआ है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, परंतु यह दुर्भाग्य ही है कि इस देश के संविधान की शपथ लेकर भी उस संविधान के पहले अनुच्छेद को न ही भली भांति जानते है और न ही उसका अर्थ समझते है। यह कोई पहली दफ नहीं है बल्कि इसके पहले भी इस तरह की बयान बाजी न केवल अलग राज्य को लेकर बल्कि हिंदी भाषा के विरोध को लेकर कई बार की गई है। कुछ समय पूर्व श्रछन् के छात्र शरजील इमाम ने भी असम और तमाम पूर्वोत्तर प्रदेशों को अलग करने का आह्वान किया था तब से वह जेल में बंद है। हमें इन राज्य विरोधी ताकतों के विरूद्ध पूरी ताकत से लड़ना होगा तभी राष्ट्र की रक्षा की जा सकेगी। आवश्यक यह है कि पहले हमें राष्ट्र की संकल्पना को न केवल समझना है बल्कि यह भी भावना जागृत करनी होगी कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरूष है यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जियेंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। अटल जी की ये पंक्तियां हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं प्रेम की भावना जागृत करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

चुनावी जंग में यूपी के दो लड़के फिर संग-संग, क्या वोटों का हो पाएगा संगम?

अंकित सिंह

एक साथ आने के सात साल बाद, यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को आगरा में फिर से मिले। राहुल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष की उपस्थिति ने 2017 की यादें ताजा कर दीं जब उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए एक गठबंधन किया था। हालांकि, गठबंधन को सफलता नहीं मिल पाई और एसपी ने केवल 47 सीटें जीतीं, जो 2012 में सत्ता में आने पर जीती गई 224 सीटों से भारी गिरावट थी, जबकि कांग्रेस की सीटें 2012 में 28 से गिरकर सात हो गईं। इसके बाद दोनों दलों के रास्ते अगल-अलग हो गए। लोकिन एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के तहत होनों दल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध दूर हो गया है। दोनों पार्टियों ने 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया गठबंधन) के तहत सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी गई, जिसके तहत राज्य की 80 सीट में से कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सहित 17 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जबकि राज्य की बाकी 63 सीटों पर सपा और गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सहित 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सपा ने मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर किया था जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। आगरा में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में अखिलेश यादव के शामिल होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि 'इंडिया' 'जनबंधन' 'अन्याय काल के अंधेरे' को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगरा में रोड शो के दौरान राहुल और अखिलेश ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी मौजूद थीं। अखिलेश ने आगरा में अपने संबोधन में 'भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ' का नारा देते कहा, ''आज लोकतंत्र और संविधान संकट में है। भाजपा सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है। संविधान विरोधी काम कर रही है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को जो हक दिया था उसे भाजपा सरकार ने छीना है। राहुल ने अपने संबोधन में कहा, ''मैं, प्रियंका और अखिलेश मिलकर नफरत को मिटाने निकले हैं। ये देश मोहब्बत का है। पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की है। नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे।'' दोनों दलों के नेताओं ने यह भी कहा कि 2017 और 2024 के बीच एक बड़ा अंतर है। हमने अतीत से सबक लेते हुए इस बार गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के पास नेतृत्व के रूप में लोग हैं, जो इसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस की संगठनात्मक खामियों ने 2017 में गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। इस बार स्थिति हमारे पक्ष में है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 2017 की तुलना में, यूपी के लड़के अब राजनीतिक नौसिखिए नहीं हैं। जबकि अखिलेश ने अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव सहित अधिकांश वरिष्ठ नेताओं की इच्छाओं के खिलाफ गठजोड़ करने से पहले केवल कुछ महीनों के लिए अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था, राहुल तब कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि भाजपा विरोधी वोट अब एक साथ हो गए हैं। एमवाई समीकरण को मजबूती मिली है। इसके अलावा जो लोग केंद्र और राज्य सरकार से नाराज है, उन्हें भी अपने पाले में लिया जा सकता है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी हाल में ही भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राज्य में ओबीसी को लेकर खूब बात की और जाति आधारित जनगणना कराई जाने की मांग की। कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी को पिछड़े वोट का फायदा भी हो सकता है।

घंटों बैठे रहने पर भी पेट नहीं होता साफ

निपटने के लिए फॉलो करें ये घरेलू नुस्खे

दिनभर चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए पेट का साफ रहना जरूरी होता है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। सुबह पेट साफ न होने की कई वजह हो सकती हैं। जैसे शरीर में पानी की कमी, खाना-खाने का गलत समय, नींद पूरी न होना और गलत खान-पान। पेट साफ न होने की समस्या से पीड़ित लोग दिनभर गैस-एसिडिटी, पेट दर्द और सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इस परेशानी से निपटकर एक ही बार में पेट साफ करने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं।

एक बार में पेट साफ करने के लिए तुरंत अपनाएं ये चीजें

1) पेट साफ करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खूब पानी पीना शुरू कर दें। ऐसा करने पर शरीर से सभी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके लिए सुबह सबसे पहले गुनगुने पानी को पीएं।
2) पेट साफ करने के लिए फाइबर से भरपूर चीजों को खाने में शामिल करें। ये आपके पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। फाइबर से पूर्ण चीजें मल त्याग को सही और नियमित रखती हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, गाजर, अमरूद जैसी चीजें फाइबर से भरपूर होती हैं।
3) कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए सेब, नींबू और एलोवेरा जैसे फलों और सब्जियों के रस के मिक्स में पोषक तत्व होते हैं। ऐसे में ये जूस कोलन मूवमेंट को ट्रिगर करके, पेट को साफ करते हैं।
4) एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा है और अपच की समस्य हो तो पेट साफ करने के लिए आप एक गिलास गर्म पानी के साथ एक चम्मच हींग पाउडर डालकर पी सकते हैं।
5) पेट के लिए दही रामबाण मानी जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड पेट की समस्याओं में फायदा देता है। ऐसे में रोजाना की थीली में दही को शामिल करें या फिर खाने के बाद एक कटोरी दही खाएं या छाछ पीएं।

बदलते मौसम में इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 सब्जियां

बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरुरी है, इस मौसम बीमारियां ज्यादा फैलती है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण सर्दी-खांसी और बुखार जैसी बीमारियां होने लगती है। बदलते मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन सब्जियों का सेवन जरुर करें। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए इन सब्जियों का सेवन जरुर करना चाहिए।

बदलते मौसम में हर व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती है। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से व्यक्ति घिर जाता है। बदलते मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरुरी है और इससे आपकी बॉडी को बीमारियों से लडने की मदद मिलती है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए लोग कई चीजों का सेवन करते है। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए इन सब्जियों का सेवन जरुर करना चाहिए। आइए आपको बताते है बदलते मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए इन 5 सब्जियों का सेवन करें।

पत्तेदार सब्जियां खाएं

बदलते मौसम में इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इस मौसम में आप पालक या केल का सेवन कर सकते हैं।

लौकी की सब्जी खाएं

लौकी सब्जी अगर घर में बन जाए तो सभी लोग इसे खाने के लिए मुंह टेढ़ा करते हैं क्योंकि लौकी हर किसी को पसंद नहीं होती। हालांकि लौकी में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए और विटामिन के पाए जाते है। इसके साथ ही लौकी में पानी और फाइबर की मात्रा काफी होती है। लौकी खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही पाचन में भी सुधार होता है, आप इसका जूस भी पी सकते हैं।

ब्रोकली का सेवन करें

ब्रोकली स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती, इसमें विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व होते है। ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते है जो पाचन से जुड़ी समास्याएं दूर करती है। इसके साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत करती है। आप रोजाना ब्रोकली की सब्जी, सूप और सलाद खा सकते हैं।

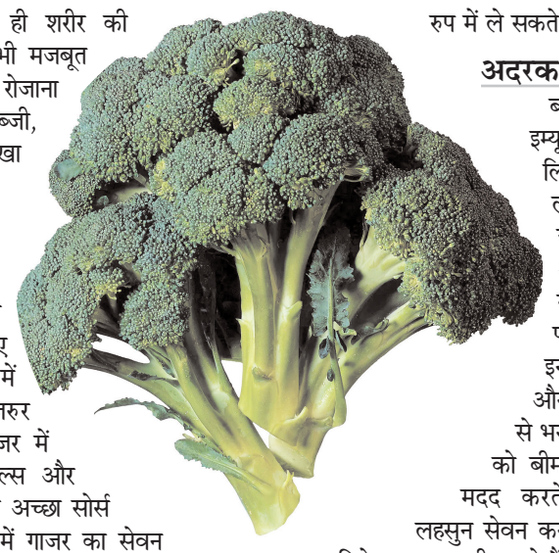

गाजर का सेवन करें

इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए अपनी डाइट में गाजर को जरुर शामिल करें। गाजर में विटामिन्स, मिनरल्स और बीटा कैरोटीन का अच्छा सोर्स होता है। सर्दियों में गाजर का सेवन करना काफी अच्छा माना जाता है। गाजर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। गाजर का सेवन सब्जी, जूस, सलाद या सूप आदि के रुप में ले सकते हैं।

अदरक और लहसुन

बदलते मौसम में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक और लहसुन का सेवन जरुर करना चाहिए। अदरक और लहसुन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते है। इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर होते है, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।अदरक और लहसुन सेवन करने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं।

● दिव्यांशी भदौरिया

जौ घास कई बीमारियों को रखे दूर, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

बहुत सालों से जौ की खेती हो रही है। जौ एक ग्लूटेन फ्री अनाज है, जौ घास सिर्फ घास नहीं है। यह एक सुपरफूड है। जौ की घास बहुत ही फायदेमंद और कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जौ की घास में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। जौ की घास का रस आसानी से पचने योग्य होता है। बार्ली ग्रास का सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। जौ की घास का रस वजन घटाने में भी सहायक होता है। आइए जानते हैं जौ घास के कितने फायदे हैं-

वजन घटाने में सहायक

पोषण विशेषज्ञ के अनुसार, जौ घास का रस मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन घटाने में सहायता करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और कैलोरी कम होने के कारण यह वजन को मैनेज करने में सहायक होता है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

जौ घास का रस प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखता है और शरीर को अनेक बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है। यह रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। जौ घास का जूस एंटीजन का पता लगाने में सहायता करता है और एंटीजन के संपर्क में आने पर बीमारी को रोकने के लिए शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।

मधुमेह को करता है कंट्रोल

जौ घास के रस में भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जो फास्टिंग ब्लड शुगर कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद हैं। जौ घास में सैपोनारिन पाया जाता है, जो भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित कर सकता है। एक्सपर्ट की सलाह पर मधुमेह के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं।

लिवर की करता है सफाई

जौ घास में क्लोरोफिल होता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और लीवर की सफाई करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें कई एंजाइम होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। इनके अलावा जौ घास में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आंतों की परत को ठीक करके पेट और आंत के रोगों का इलाज करते हैं।

त्वचा के लिए फायदेमंद

जौ घास एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है। जौ घास का रस शरीर को फ्री रेडिकल्स से निपटने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है, जो हमारी त्वचा के फायदेमंद होती है।

ब्लड प्रेशर को करता है नियंत्रित

जौ घास ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद माना जाती है। जौ घास में बहुत ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते है। एक्सपर्ट की सलाह पर ब्लड प्रेशर के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं।

पुरुषों को सेहत का ध्यान रखने के लिए जरूर करने चाहिए ये 4 योगासन

लोग बढ़ते तनाव और गलत खान-पान की आदतों की वजह से कई समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है, वह है थकान। खासकर पुरुष इस बात की शिकायत करते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो रूटीन में ये 4 योगासन शामिल करें। जानिए योगासन और करने का तरीका-

वसिस्थासना

ये आसन एक तरह का साइड प्लैंक है। जिसे शुरु करने के लिए, अपने दाहिने हाथ को फर्श से उठाएं और अपनी बायीं हथेली को जमीन पर टिकाएं, अपने पूरे शरीर को अपनी दाहिनी ओर मोड़ें, फिर अपने दाहिने पैर को फर्श से उठाएं और इसे अपने बाएं पैर के ऊपर से पार करें और ऊपर उठाएं। इस दौरान आपका दाहिना हाथ आपके सिर के ऊपर और आपकी उंगलियां ऊपर की ओर हो। अपने घुटनों, एड़ी और पैरों को एक साथ स्पर्श करें और चेक करें कि आपके हाथ और कंधे एक सीधी रेखा में हों।

पश्चिमोत्तानासन

इस आसन को करने से पाचन संबंधी समस्याएं और कब्ज से निपटने में मदद मिलती है। इसके लिए सबसे पहले दंडासन करें। इसके लिए आपके पैर आगे की ओर फैले हुए हों और आपके घुटने थोड़े मुड़े हुए हों। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अपने पेट से हवा बाहर निकालने के लिए सांस छोड़ें। कूल्हों के बल आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए अपने ऊपरी शरीर को अपने निचले शरीर पर रखें। अपनी बाहों को नीचे रखें और अपनी उंगलियों को अपने बड़े पैर की उंगलियों पर रखें। अपनी नाक को अपने घुटनों पर रखने की कोशिश करें।

चक्रासन

इसे करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने पैरों को घुटनों पर मोड़ें और देखें कि आपके पैर फर्श पर रखे हुए हैं। हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए हाथों को कोहनियों पर मोड़ें। हाथों को कंधों पर घुमाएं और अपनी हथेलियों को अपने सिर के पास दोनों तरफ फर्श पर रखें। सांस लें, अपनी हथेलियों और पैरों पर दबाव डालें और अपने पूरे शरीर को एक आर्च बनाने के लिए ऊपर उठाएं। अपने सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाते हुए अपनी गर्दन को आराम दें। इसे करने से पेट में जमा चर्बी को कम होती है।

नौकासन

इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। अपने ऊपरी शरीर को जमीन से 45 डिग्री ऊपर उठाएं। अपने कूल्हों को चारों ओर घुमाएं और अपने पैरों को जमीन से 45 डिग्री ऊपर उठाएं। इस समय आपकी आंखें और पैर की उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए। अपने घुटनों को मोड़ने से बचें। अपने हाथों को आगे की ओर और जमीन के सामने रखें। अपने पेट की मांसपेशियों को कस लें।

आयुर्वेदः आंखों की देखभाल के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक तरीके

खत्म हो जाएंगी आई प्रॉब्लम

आंखें हमारे शरीर के नाजुक और सबसे जरूरी हिस्सों में आती है। ऐसे में इनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। रोजाना की कुछ आदतों के चलते आंखों को काफी नुकसान होता है। कुछ लोगों को आंखों से पानी आना, दर्द, जलन, कम दिखना, कुछ देखने के लिए आंखों पर बहुत जोर डालना, सिरदर्द जैसी समस्या होती हैं। ऐसे में इन सभी लक्षणों से बचनें और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डॉक्टर दीक्षा भावसार द्वारा बताए गए तरीकों को अपना सकती हैं।

आंखों की रोशनी बढ़ाने और समस्याओं से निपटने के तरीके-

1) अपनी आंखों में गुलाब जल डालें। इससे डालने पर जलन से राहत मिलती है और आंखों को आराम भी मिलता है।
2) गाय का घी खाएं, साथ ही इसे आंखों में डालना या नाक में डालना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है।
3) सेहत के लिए त्रिफला अद्भुत जड़ी बूटी है। ये आंखों के लिए भी फायदेमंद है। आंख धोने के लिए या इसका घी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे 21 बार मोड़कर बारीक कपड़े या कॉफी फिल्टर से छान लें। ध्यान दें कि त्रिफला का कोई भी कण पानी में न रहे। एक बार जब यह छान लें तो आप इस पानी से अपनी आंखें धो सकते हैं।
4) अंजना भी एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद अंजना को द्रिकबलम यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला मानता है।
5) रिफ्लेक्सोलॉजी विज्ञान के अनुसार जब हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव हमारी दूसरी और तीसरी उंगली पर पड़ता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा तंत्रिका अंत होते हैं, जो आपकी आंखों के कामकरने के तरीके को उत्तेजित करते हैं और नजर में सुधार करते हैं।
6) 20-20-20 नियम
थकान और आंखों के स्ट्रेस को कम करने के लिए हर 20 मिनट में कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आखों का स्वास्थ्य बेहतर होता है।
7) आंखों की एक्सरसाइज
सरल तकनीकें जैसे साइड में, ऊपर और नीचे देखने वाली एक्सरसाइज करें। इसे रोजाना 10 मिनट तक आंखों को दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घुमाना फोकस और सरेखण को अनुकूलित करने में बहुत मदद करता है।

8) त्राटक एवं ध्यान करें। त्राटक का मूल रूप से मतलब है किसी विशेष वस्तु जैसे सूर्य, दीपक, आदि को कुछ दूरी से देखना। यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये नजर और यहां तक ??कि याददाश्त में भी सुधार करता है। वहीं ध्यान आपको शांत करने और शरीर में पित्त को संतुलित करने में मदद करता है। इससे आपके आंखों की रेडनेस, जलन जैसी समस्या को रोकने में मदद मिलती है। ऐसा अच्छी नींद और मन को शांत करने में मदद करता है।
9) रोजाना बहुत देर के लिए फोन की लाइट के संपर्क में आसे आंखे डैमेज हो सकती हैं। इसलिए अपनी स्क्रीन पर ब्लू लाइट फिल्टर चालू करें।
10) अच्छी नींद आंखों को आराम पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए रोजाना चैन की नींद सोना काफी जरूरी है।

आंखों में बहुत जल्दी होती है थकान?

आंखे हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है, जिसकी देखरेख हम सभी को थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। अक्सर जो लोग घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों में दर्द या जलन महसूस होने की समस्या होती है। अगर आपके साछ भी ऐसा होता है तो आपको आंखों में खिंचाव का अनुभव हो सकता है जिसे 20-20-20 रूल से ठीक किया जा सकता है। इस नियम के मुताबिक, हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के लिए आपको 20 फीट दूर किसी वस्तु को कम से कम 20 सेकंड तक देखना चाहिए। स्क्रीन टाइम से ये नियमित ब्रेक लेने पर आपकी आंखों को कुछ जरूरी राहत देते हैं और आंखों के तनाव को रोकने में मदद करते हैं।

आंखों में खिंचाव के लक्षणः

- सिरदर्द
- रोशनी के प्रति संवेदनशीलता
- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना
- आंखें खुली रखने में मुश्किल होना
- गर्दन में दर्द होना

आंखों का खिंचा को कैसे दूर करें

- अपनी आंखों को नम और फ्रेश करने के लिए बार-बार झपकाएं।
- इसके अलावा स्क्रीन से हर 15-30 मिनट में ब्रेक लें।
- अपने कंप्यूटर स्क्रीन ब्राईटनेस को एडजस्ट करें
- टेक्स्ट का साइड ठीक करें।

आंखों में जलन के लिए क्या करें

- आंखों में अगर जलन या थकान हो तो आप आंखों में पानी के छींटे डालें।
- इस समस्या से बचने के लिए हाइड्रेशन का भी ख?याल रखें और भरपूर पानी पिएं।
- आंखों की जलन दूर करने के लिए खीरे का इस्तेमाल करें। इसके लिए ठंडे खीरे को कद्दूकस करें और फिर इसे अपनी आंखों पर रथें।
- जलन से निपटने के लिए कॉटन पैड पर गुलाब जल डालें और फिर उसे आंखों पर लगाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नारण राठवा भाजपा में शामिल

अहमदाबाद। भारत में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में जीत पाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा असरदार साबित होने की बजाय पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ पकड़ लिया है। नारण राठवा का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी है। राठवा ने अपने बेटे संग्राम सिंह के साथ गांधीनगर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय कमलम् में सदस्यता ग्रहण की। आदिवासी समुदाय से आने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल इस साल अप्रैल में समाप्त होने वाला है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। वह पांच बार लोकसभा के लिए चुने गए।

ईडी ने केजरीवाल को आठवीं बार जारी किया समन

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवीं बार समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को यहां एजेंसी के मुख्यालय में चार मार्च को आने को कहा गया है। केजरीवाल इस मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए थे। यह सातवीं बार है जब केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शहर की एक अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव के दौरान लगा झटका

लखनऊ। यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडेय के साथ ही सपा के 3 अन्य विधायक बागी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडेय ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। सपा के विधायक मनोज पांडे ने पत्र में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा कि मैं मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा स्वीकार किया जाए। वहीं अमेठी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह एक गाड़ी से सदन पहुंचे। अयोध्या जनपद के सपा विधायक अभय सिंह और अंबेडकरनगर से सपा विधायक राकेश पांडेय भी मौजूद हैं। तीनों ने संयुक्त बयान में कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। बता दें कि विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी पार्टी की दोनो मीटिंग में नहीं गए थे।

क्रॉस वोटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाईः अखिलेश

लखनऊ। राज्य सभा चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बात कही। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के जितने भी साथी है, उनका कहना है ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए साहस की जरूरत है। सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडेय पर पूछ के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक कद्दावर लग रहे थे, लेकिन कद्दावर निकले नहीं ये बात समझ में आ गई है। सपा अध्यक्ष ने पल्लवी पटेल पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अभी तक आई नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि वोट दिया होगा या नहीं। मैं किसी की अंतरआत्मा के बारे में नहीं जान सकता है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा के पक्ष में वोटिंग न करने वाले विधायकों को बारे में कहा कि किसी को सिक्योरिटी मिली होगी, किसी को धमकाया गया होगा।

हिमाचल में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग!

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर राज्य की एकमात्र सीट पर मुकाबले को मजबूर कर दिया है। जबकि कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के 25 विधायक हैं, चुनाव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। दावा किया जा रहा कि हिमाचल प्रदेश में क्रास वोटिंग हुई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अफवाहों पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मेरी अंतरात्मा साफ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने कहा कि जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे और स्थिति का सामना करेंगे। हम नैया पार लगा लेंगे, हमारे पास बहुमत है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने चुनाव के लिए मतदान किया है। मुझे उम्मीद है कि उन सभी ने पार्टी की विचारधारा पर वोट किया होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला

लेफ्ट चाहती है वायनाड से बाहर हो जाएं राहुल

तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन में आपस में ही विवाद छिड़ा हुआ है। लेफ्ट पार्टी की ओर से वायनाड सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्ट चाहती है कि वायनाड से राहुल गांधी बाहर हो जाएं। बता दें, राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। इसके बाद भी लेफ्ट ने इस सीट से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चार महत्वपूर्ण सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेफ्ट ने पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है।

सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने कभी किसी राज्य को वोट बैंक के नजरिये से नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में केरल को बीजेपी शासित राज्यों की तरह विकास का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई है लेकिन मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है। कांग्रेस और उसके अन्य कम्युनिस्ट गठबंधनों की एक ही प्राथमिकता है। उन्होंने केवल अपने परिवार को देश पर शासन करने दिया। उनके लिए उनके परिवार का कल्याण भारतीयों के कल्याण से बेहतर है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि केरल में वे एक-दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन केरल के बाहर वे बीएफएफ हैं।। यानी हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त।

पीएम मोदी ने सभा में बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ये है मोदी गारंटी। पीएम मोदी ने केरल के लोगों से कहा कि आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करूंगा। ये मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष मान चुका है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीतेगा इसलिए उसकी रणनीति है कि मोदी को बुरा-भला कहो। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति को लेकर विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है इस कारण वो सरकार को भला-बुरा कहने की रणनीति अपना रहा है। पीएम मोदी ने सेंट्रल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की

राज्य इकाई की पदयात्रा के समापन समारोह में केरल के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी लोकसभा चुनावों में राज्य में उनकी पार्टी को दोहरे अंकों में सीट जिताकर अपना आशीर्वाद दें।

विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है : मोदी

प्रधानमंत्रीन नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के लोगों में एक नया उत्साह है। 2019 में केरल के लोगों के दिलों में जो उम्मीद उभरी थी, वह अब 2024 में उनका विश्वास बन गई है। उन्होंन कहा कि 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केरल में दोहरे अंक में वोट मिले। ऐसा लग रहा है कि 2024 में केरल ने दोहरे अंक में सीटें देने का फैसला कर लिया है। कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है, यह अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। 2019 में, शहर में चर्चा थी फिर एक बार, मोदी सरकार; 2024 में हर तरफ चर्चा का विषय है अबकी बार, 400 पार।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उसके पास भारत के विकास का कोई रोडमैप नहीं है। इसका केवल एक ही एजेंडा है- मोदी को श्राप दो। केरल ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। केरल भाजपा और एनडीए को आशीर्वाद देगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी आपकी आकांक्षाओं और सपनों को हकीकत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और, ये है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी भारत के किसी भी राज्य को वोट बैंक की नजर से नहीं देखा। जब केरल में भाजपा मजबूत नहीं थी, तब भी हमने केरल को सशक्त बनाने के लिए दिन-रात काम किया।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास का उतना ही लाभ केरल को मिला है जितना भाजपा शासित राज्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि हर कोई मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। ये है मोदी की गारंटी। हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और अधिक परिभाषित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल में शिक्षा प्रणाली के साथ क्या किया है। केरल के गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान किस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हर कोई जानता है।

मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल केरल में शैक्षणिक संस्थानों के विकास पर काम करेगा। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों के लिए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंन कहा कि केरल की राज्य सरकार के लगातार असहयोग के बावजूद केरल भारत सरकार की प्राथमिकता पर रहा है। भारत सरकार ने ही तय किया है कि केंद्र सरकार की सारी नौकिरियों की परीक्षाएं मलयालम समेत सभी स्थानीय भाषाओं में कराई जाए।

पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की

गौरतलब है कि पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को केरल की यात्रा पर हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तीन प्रमुख तकनीकी इकाइयों का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा भी की जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने वीएसएससी में बताया कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप एवं अजीत कृष्णन और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हैं। पीएम मोदी ने चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख भी दिए।

वायनाड सीट को लेकर बृंदा करात ने दी बड़ी नसीहत

राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की जरूरत है: सीपीआई

नईदिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने सोमवार को घोषणा की कि वरिष्ठ नेता एनी राजा केरल में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगी। यह सीट अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास है। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं। वह सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। वह सीपीआई की महिला शाखा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है लेकिन संभावना है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और एनी राजा के खिलाफ लड़ेंगे।

इसी को लेकर सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सीपीआई ने वायनाड सीट से महिला आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली कॉमरेड एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब वह पूरे एलडीएफ की ओर से उम्मीदवार होंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। करात ने कहा कि केरल में अगर आप आते हैं और वामपंथ के खिलाफ लड़ते हैं तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? इसलिए उन्हें अपनी सीट के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है।

हालांकि सीपीआई कांग्रेस के साथ विपक्षी इंडिया गुट का सदस्य है, जिसने 2019 के चुनावों में वायनाड सीट 4.3 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीती थी, वामपंथी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से राहुल से आगामी चुनाव किसी अन्य सीट से लड़ने के लिए कहा है। एनी राजा ने कहा कि पिछले 40-45 वर्षों में पार्टी ने मुझे कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी हैं। मैं महिलाओं के बीच भी काम कर रही हूं, उन्हें एकजुट कर रही हूं और उनके मुद्दे उठा रही हूं। अब पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है।

केरल में, यह कई वर्षों से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) बनाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) रहा है। 2019 में भी सीपीआई ने वायनाड सीट पर चुनाव लड़ा था। एलडीएफ गठबंधन में सीपीआई को चार सीटें दी गई हैं और वायनाड उनमें से एक है। अन्य सीटें तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और मवेलिककारा हैं। सीपीआई ने पिछली बार भी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। केरल में, यह एलडीएफ बनाम यूडीएफ है, और राज्य में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है।

बिहार में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका

पटना। बिहार में राजद के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरव और राजद विधायक संगीता कुमारी आज भाजपा में शामिल हो गईं। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए बडी राहत की बात है। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वह चेनारी से विधायक है। इसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ की बात करें तो वह विक्रम विधानसभा से विधायक हैं। वह काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे थे। उन्होंने भी पाला बदल दिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

जायसवाल ने टेस्ट में रचा इतिहास ब्रैडमैन के क्लब में हुए शामिल

रांची। इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने पांच विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने इस जीत के साथ सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने विरोधी टीम के खिलाफ लगातार दो दोहरे शतक के साथ दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। इसी के साथ वह दिग्गज क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के क्लब में शामिल हो गए हैं।

पिछले साल वेस्टइंडीज दौरे पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले युवा बल्लेबाज ने अब तक आठ टेस्ट मैच खेले हैं। अपनी 15 पारियों में उन्होंने 971 रन बनाए, ऐसा करने वाले वह दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने शुरुआती आठ टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 1210 रन बनाए हैं।

23 वर्षीय बल्लेबाज ने शुरुआती आठ टेस्ट मैचों में 800 से अधिक रन बनाकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया है। गावस्कर ने शुरुआती आठ टेस्ट मुकाबलों में 938 रन बनाए। इस लिस्ट में वह चौथे नंबर पर शामिल हैं। तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर एवर्टन वीक्स का नाम दर्ज है जिन्होंने 11 पारियों में 968 रन बनाए। वहीं, पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील 15 पारियों में 927 रन के साथ इस लिस्ट में शामिल होने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं।

यशस्वी भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी भी बन गए। कोहली, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ अपने करियर के में दो-दो बार ऐसा कर चुके हैं। इनके अलावा दिलीप सरदेसाई ने भी एक टेस्ट सीरीज में 600 रन का आंकड़ा पार किया है। जायसवाल ने चार मुकाबलों में 655 रन बना लिए हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 73 हजार के पार निफ्टी 22,200 के करीब पंहुचा

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार एक दिन पहले गिरावट से उबरते हुए मंगलवार को हरे निशान में लौट आया और उतार-चढ़ाव भरे करोबार में चढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज अपने पिछले बंद भाव 72,790.13 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 72,723.53 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 72,660.13 के नीचले और 73,161.30 के इंट्रा-डे हाई लेवल तक गया। अंत में सेंसेक्स 0.42 प्रतिशत या 305.09 अंक की बढ़त के साथ 73,095.22 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 18 के शेयर हरे जबकि शेष 12 के स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.34 प्रतिशत या 76.30 अंक चढ़कर 22,198.35 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी की 28 कंपनियों के शेयर प्रॉफिट में जबकि 22 गिरावट के साथ बंद हुई।

रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल की योजना को एनसीएलटी ने दी मंजूरी

नईदिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के लिए बोली के दूसरे दौर में जून 2023 में आईआईएचएल (इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत योजना को मंजूरी दे दी। इस मामले में विस्तृत आदेश आज दिन में आने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2021 में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी द्वारा प्रशासनिक मुद्दों और भुगतान चूक पर रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को हटा दिया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था।

स्टार्टअप नए भारत की रीढ़, यह हमारा समय है : गोयल

नईदिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उद्यमियों से आह्वान किया कि वे 'चूकें नहीं' और अधिक से अधिक अवसरों का लाभ उठाएं क्योंकि भारत 2047 तक 35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक अगुआ के रूप में उभरा है और इसकी कहानी आत्मविश्वास, सुशासन और निरंतर नवाचार की है। केंद्रीय मंत्री ने आगामी 'स्टार्टअप महाकुंभ' के लिए एक उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, मेरा मानना है कि स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ बनेंगे। यह हमारा समय है। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि हम नहीं चूकेंगे। मुझे आशा है कि सभी स्टार्टअप्स को यह संदेश स्पष्ट रूप से जाएगा कि वे इस अवसर को न चूकें। उन्होंने कहा कि आगामी व्यापक कार्यक्रम देशभर में चल रही स्टार्टअप क्रांति को प्रदर्शित करेगा। गोयल ने विश्वास जताया कि युवा भारतीय 'अमृत काल' में देश की नियति को आकार देंगे।

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलते ही टूट पड़े निवेशक

नईदिल्ली। रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जोरदार रिस्पांस के चलते प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलने के पहले घंटे के भीतर ही पूरी तरह से बुक हो गया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, प्लेटिनम आईपीओ 12:52 बजे तक 3.20 गुना सब्सक्राइब हो गया। प्लैटिनम आईपीओ के रिटेल हिस्से को अब तक 4.53 गुना और एनआईआई हिस्से को 4.34 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्से अभी तक 0.01 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ मंगलवार, 27 फरवरी को बोली लगाने के लिए खुल गया है और यह गुरुवार, 29 फरवरी तक सब्सक्राइब करने के लिए खुला रहेगा। प्लैटिनम आईपीओ ने सोमवार, 26 फरवरी को एंकर निवेशकों से 70.59 करोड़ रुपये जुटा लिए।

क्या एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है उत्तर प्रदेश?

अनिल सिंह

जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है। क्या उत्तर प्रदेश में यह क्षमता है, वह भी तब जब इसकी पहचान एक पिछड़े और बीमारु राज्य के तौर पर रही हो? अपराध और माफिया जिस राज्य की पहचान रहे हों, निवेशक जिधर देखना पसंद ना करते हों, क्या वह उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी देख सकता है कुछ साल पहले तक तो इस सवाल का जवाब ना में होता, लेकिन मोदी योगी के डबल इंजन शासन में राज्य इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है।

जिस राज्य ने आर्थिक सुधारों की बदौलत सात सालों में अपनी जीडीपी को 12.47 लाख करोड़ से बढ़ाकर 26 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, वह राज्य यह सपना देख सकता है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना आसान नहीं है।

उत्तर प्रदेश को 1991 के कल्याण सिंह के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाये तो उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 तक ऐसा ही था। माफिया सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में अपराध उन्मूलन और संगठित माफिया गिरोह के खिलाफ जब गोली और बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तब राज्य के लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि सत्ता संचालित करने वाले अपराधियों को भी रौंदा जा सकता है। योगी सरकार ने जब माफिया गिरोहों पर अंकुश लगाकर उद्योग और निवेश का माहौल बनाना शुरू किया तब उद्योगपतियों का विश्वास सरकार पर बढ़ा। सरकार के कार्यशैली पर भरोसा बढ़ने के बाद दीपक बजाज ने गोरखपुर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीयल अथॉरिटी में

50 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर 2021 में प्लॉट नंबर के-29 पर सक्षम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। सक्षम एग्रो कंपनी प्रतिदिन सवा लाख से ज्यादा बोरियों का उत्पादन कर रही है, और सैकड़ों लोगों को नौकरी और रोजगार दे रही है।

दीपक बजाज 2021 से पहले भी निवेश करने और रोजगार देने में समक्ष थे, लेकिन तब किसी मुख्यमंत्री या सरकार को दीपक बजाज जैसे उद्योगपति की शायद जरूरत ही नहीं थी परंतु बीते सात सालों में उद्योग एवं उद्योगपतियों की महत्ता को प्रदेश ने समझा है। इस बदलती फिजा का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को 10 लाख करोड़ की 14,000 से ज्यादा उद्योग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिये हुआ निवेश प्रदेश के 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने में सफल होगा।

आर्थिक सुधारों एवं निवेश की बदौलत बीते सात वर्षों में उत्तर प्रदेश बड़ी छलांग लगाते हुए महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य बन चुका है। वर्ष 2018 के फरवरी महीने में जब योगी सरकार ने पहली बार यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, तब विपक्षी दल उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन सरकार अपने प्रयासों में जुटी रही। पहले इन्वेस्टर समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले।

अगले पांच महीने में 61,700 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। जुलाई 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 67,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। कोविड के दौर में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतारने में सरकार को सफलता मिली।

सरकार के इन्हीं प्रयासों से दीपक बजाज जैसे अनगिनत उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हुए। उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाने के लिये केवल निवेश पर ही निर्भर नहीं है। वह राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश 12 एक्सप्रेस वे वाला एकलौता राज्य होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं काशी-मथुरा में देवालयों के जीर्णोद्धार से राज्य में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, दुबई में सिल्वर मेडल विजेता सुश्री स्नेहा बंजारे ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर सुश्री बंजारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल करना गौरवान्वित करने वाला है। इससे प्रदेश का मान बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में ऋण क्षमता 75,810 करोड़

मंत्री नेताम ने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ अधिक सहयोग करने बैंकों से किया आह्वान

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राजधानी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में छत्तीसगढ़ के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2024-25 का आयोजन किया. कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने राज्य फोकस पेपर (2024-25) का अनावरण किया.

कार्यक्रम में डॉ. ज्ञानेंद्र मणि, सीजीएम नाबार्ड ने अपने संबोधन में राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 75,810 करोड़ रुपये के प्राथमिक क्षेत्र के ऋण अनुमानों पर प्रकाश डाला. उन्होंने क्रेडिट प्लानिंग प्रक्रिया में स्टेट फोकस पेपर के महत्व और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों में

नाबार्ड द्वारा की गई पहलों को भी रेखांकित किया.

वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण क्षमता 75,810 करोड़ रुपये अनुमानित है. जिसमें से कृषि का हिस्सा 31,969 करोड़ रुपये है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संबंध में 39,046 करोड़ रुपये की संभाव्यता का आकलन किया गया है. एवं अन्य प्राथमिक छेत्र मे 4795 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है.

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने नाबार्ड की भूमिका की सराहना की और राज्य ऋण संगोष्ठी 2024-25 के आयोजन के लिए नाबार्ड को सम्मानित किया. कृषि उन्नति योजना जैसी राज्य सरकार के की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ अधिक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने सभी हितधारकों को उनके समर्थन के लिए बधाई दी और बैंकों से अनुरोध किया कि वे जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अपना पूरा समर्थन दें.

जग्गी हत्याकांड : हाईकोर्ट में अधूरी रही सुनवाई

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई अधूरी रही. इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी. बता दें कि 4 जून 2003 में एनसीपी नेता विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी रहे जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम अजीत जोगी, अमित जोगी समेत कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया था. अजीत जोगी और अमित जोगी की गिरफ्तारी भी हुई थी. बाद में अमित जोगी समेत अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया था. यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में लगा था. इस पर आज सुनवाई अधूरी रह गई. कल फिर मामले की सुनवाई होगी.

मवेशी चारा कम खाए और गोबर ज्यादा दिए कैसे ?

भाजपा विधायक ने लगाए गड़बड़ी के आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन गोबर और पैरा परिवहन में गड़बड़ी का मामला उठा। कांग्रेस शासन काल में गोबर खरीदी और दान में मिले पैरा के परिवहन में हुए करोड़ों के खर्च पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और लता उसेंडी ने प्रश्न किया और बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए। जवाब देते हुए सदन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जांच विधानसभा की प्रश्न एवं सदर्भ समिति से कराने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डा. ने इसकी स्वीकृति दे दी।

अजय चंद्राकर ने पूछा कि गोठानों में पैरा परिवहन में 14वें-15वें वित्त आयोग का पैसा लगाया गया, वित्त आयोग की राशि को ऐसे काम में लगाने का नियम क्या है? उन्होंने कहा कि मैं प्रमाण दे सकता हूं कि इसमें शेष राशि से पैसे खर्च हुए हैं। इस पर बृजमोहन ने कहा कि पैरा दान में मिला है। इसका परिवहन छोटी गाड़ियों व ट्रैक्टरों के माध्यम से 285 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक में किया गया है। इसके लिए बजट में प्रविधान है। अधिकारियों से जांच करा लेंगे।

इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि अधिकारियों से जांच करवाने पर उसकी हेराफेरी हो जाएगी। इसके बाद बृजमोहन ने कहा कि प्रश्न एवं सदर्भ समिति के माध्यम से जांच कराएंगे। इसके बाद कोंडागांव की भाजपा विधायक लता उसेडी ने जितने मवेशी नहीं उससे ज्यादा गोबर बेचने और खरीदने का मामला उठाया। उन्होंने जांच कराने की मांग की। इस पर विधानसभा

अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने कहा कि मूल प्रश्न यह है कि चारा कम खाए और गोबर ज्यादा कैसे दिए?

लता उसेंडी ने कहा कि शराब का पैसा कहां-कहां पहुंचा है, वह तो सबको पता है। गोबर का पैसा कहीं-कहीं पर पहुचा है इसकी जांच कराएंगे क्या ?, इस पर अध्यक्ष डा. रमन ने कहा कि किस नस्ल की गाय या भैंस है उसकी जांच करानी पड़ेगी। यह प्रश्न गंभीर है। इस पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम की अनुपस्थिति में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्न एवं सदर्भ समिति के माध्यम से जांच कराएंगे।

सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने माझी समाज के जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक त्रुटि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक 10 साल के बच्चे ने कहा हमारा जाति प्रमाण पत्र बना नहीं है तो स्कूल जाकर क्या करूंगा?, माझी समाज के जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक प्रक्रिया के वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया और केंद्र की सरकार इस मामले में संवेदनशील है। हमारी विष्णु देव सरकार भी संवेदनशील सरकार है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही संबंध में पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। प्रश्न काल में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने अरहर, उड़द, मूंग एवं अन्य दलहनी के लिए खरीदी केंद्र मामला उठाया । इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्र बनाए जाते हैं।

विधानसभा में किसानों को दिए जा रहे बीज की गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठाया गया कि विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के प्रश्न पर विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ये विष्णुदेव सरकार है किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके बाद जवाब देते हुए मंत्री बृजमोहन ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को उनका हक दे रही है। नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने पूछ लिया कि पहले यह तय करें कि किसी सरकार है। कोई विष्णुदेव की कहता है तो कोई भाजपा की। इस पर बृजमोहन ने कहा कि यह सरकार मोदी की भी है, भाजपा की भी है, यह कमल फूल की भी सरकार है और यह जनता की सरकार है और यह आपकी भी सरकार है।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने उठाया फ्लाई ऐश उत्सर्जन का मामला

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रश्न काल में ही फ्लाई ऐश उत्सर्जन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ और कोरबा के औद्योगिक घराने राखड़ का सही निपटारा नहीं कर रहे। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा है। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। राखड़ से दिल की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी सांस की बीमारी इन राखड़ में मौजूद रसायन से लोगों के बीच पहुंच रही है। रायगढ़ और कोरबा में बिना इजाजत के राखड़ सड़कों में फेंकी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी स्पेसिफिक जगह की कोई शिकायत हो तो दिजिए। नेता प्रतिपक्ष के जो सुझाव आए हैं उस पर विभाग विशेष रूप से ध्यान देकर अमल करेगा।

कवर्धा में हत्याकांड का मामला भी गूंजा

नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने सदन में शून्यकाल में कवर्धा हत्याकांड का मामला उठाया है। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि कवर्धा में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल, विक्रम मंडावी, द्वारकाधीश यादव ने भी कहा, कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर है। गृहमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि रविवार को कवर्धा एसपी कार्यालय के सामने एक मकान में मां और बेटी की खून से लथपथ सड़ी-गली लाश मिली थी। जिसके

पांच सालों में छग में मानव तस्करी के 176 मामले

रायपुर. आज विधानसभा के 16वां दिन हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों कोई लेकर तनातनी देखने को मिली तो विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आएं। इसी बीच प्रदेश भर से लापता लोगों के मामले को लेकर भाजपा के सदस्य अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण भी लाया। सदन की कार्रवाई के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा प्रदेश में लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने इससे जुड़े सवाल भी किये। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीते पांच साल में मानव तस्करी के 176 मामला दर्ज किया गया है। मानव तस्करी में लापता 744 में से 740 को रेस्क्यू किया गया है। 421 आरोपियों की गिरफ्तारी, 26 प्रकरण, 50 कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि बीते 33 माह में 46 हजार 746 लोगों की सूचना दर्ज की गई। अवयस्क 9 हजार 997 में से 8 हजार 892 को वापस लाया गया है। 27 हजार 623 में से 20 हजार 485 महिलाओं को वापस लाया गया है, ऑपरेशन मुस्कान चलाकर 51 बालक 453 बालिकाओं को वापस लाया गया है।.

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

मीसाबंदी पेंशन: भाजपा-संघ के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मीसाबंदी पेंशन योजना शुरू करने पर सवाल उठाए? उन्होंने कहा कि मीसा बंदी पेंशन योजना यानी भाजपा और आरएसएस के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना है। ये छत्तीसगढ़ की खजाने की सरकार के सरक्षण में होने वाली संगठित लूट है। भाजपा के 15 साल के शासनकाल के दौरान भी मीसा बंदियों को पेंशन देने के नाम से आरएसएस और भाजपा के लोगों को करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ दिया गया था और प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा भूखे रहे एवं भाजपा और संघ के जुड़े लोग मलाई खाते रहे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार के दौरान से चल रही मीसाबंदी पेंशन के नाम से छत्तीसगढ़ के खजाने में चल रही लूटपाट को कांग्रेस की सरकार ने रोका था और मीसा बंदी पेंशन में होने वाले फिजूल खर्च को रोककर जनहित में खर्च किया गया था। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय की सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है। गोबर खरीदी को बंद कर दी गई है किसान न्याय योजना,कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को बकाया क़िस्त का भुगतान नहीं कर रही है लेकिन आरएसएस और भाजपा के प्रचारकों को लाभ पहुंचाने के लिए मीसा बंदी पेंशन को फिर शुरू कर रही है.

प्रधानमंत्री का 5 प्रतिशत गरीब होने का आंकड़ा झूठा और भ्रामक

रायपुर। देश में गरीबी को लेकर प्रधानमंत्री के दावों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अपनी नाकामियों पर परदेदारी करने, दुर्भावना पूर्वक आंकड़े छुपाना और एजेंसियों पर अनुचित दबाव बनाकर आंकड़े परिवर्तित करने वाली मोदी सरकार अब कोरी लफ्फाजी पर उतर आई है। हकीकत यह है कि विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में गरीबी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों में ही देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे धकेल दी गई है जिन्हें 5 किलो राशन देने का दावा केंद्र की मोदी सरकार करती है। 137 करोड़ की कुल आबादी में मोदी सरकार के दावों के अनुसार ही 81 करोड़ 25 लाख से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने मजबूर है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह आंकड़ा कुल आबादी का महज 30 से 32 प्रतिशत हुआ करता था जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। मोदी सरकार के अदानी परस्त नीतियों के चलते गरीब और गरीब होते गए और मध्यम वर्ग के लोग भी बड़ी तेजी से गरीबी रेखा से नीचे धकेल जा रहे हैं। देश के संसाधनों पर चंद पूंजीपति मित्रों का कब्जा तेजी से बढ़ रहा है।

कविता प्राण लहरे पर आरोप भाजपा का सांप्रदायिक चरित्र

रायपुर। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे के मसीही समाज के एक कार्यक्रम के वीडियों पर भाजपा द्वारा किये गये बयानबाजी को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने स्तरहीन और अमर्यादित बताया है। कविता प्राण लहरे एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि सभी समाजों धर्मों जातियों के कार्यक्रमों में समभाव से जाता है तथा प्रजातंत्र में सभी की भावनाओं का आदर करना है। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। विधायक कविता प्राण लहरे ने भी मसीही समाज के कार्यक्रम में उस समाज की भावनाओं का आदर करते हुये शामिल हुई थी। भाजपा अपने सांप्रदायिक चरित्र के अनुसार इस मामले में निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। शुक्ला ने कहा कि विधायक कविता प्राण लहरे बाबा गुरु घासी दास जी के अनुयायी है बाबा गुरु घासी दास जी ने दुनिया को मनखे-मनखे एक समान का संदेश दिया है। समाज मे फैले भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़ी पिछड़ी की द्वेष नकारात्मक को खत्म किया है। कविता प्राण लहरे बाबा घासी दास जी के बताये मार्ग में चलकर सभी धर्म संप्रदाय समाज को समान नजर से देखते हैं सबका सम्मान करती है ऐसे में भाजपा जिसका मूल काम नफरत और वैमनस्यता फैलाना है।

बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रमोद ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने राजधानी में लगातार बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुए आज एसपी रायपुर को एक ज्ञापन सौंपा और इस पर तत्काल

नियंत्रण के साथ आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और हाईकोर्ट द्वारा डी.जे. के संबंध में पारित आदेश की अवहेलना पर भी उन्होने ध्यान उल्लेखित किया। श्री दुबे ने कहा कि जब राजधानी रायपुर में ये हाल तो पूरे प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर में कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब दो-चार मोहल्लों में चाकूबाजी की वारदात न हुई हो। चेन स्नेचिंग,मोबाईल व पर्स लूट जैसी सरेराह अपराध तो आम बात है। चंगोराभाठा, बीएसयूपी कॉलोनी, बस स्टैण्ड भाटांगाव, भीमनगर जैसे क्षेत्रों में आये दिन नशे की आड़ में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जिस अपराधी का पुलिस जुलूस निकालकर हिस्ट्रीशीटर बताती है, उसके विपरीत धार्मिक आयोजनों पर वही पोस्टर में दिखाई पड़ते है जो सभ्य समाज के लिये कलंक है। अत: ऐसे लोगों के खिलाफ सक्त कार्यवाही किये जाने निर्देश देने का कष्ट करें। वर्तमान में परीक्षा का समय नजदीक है लेकिन सड़कों में आये दिन डी.जे. एवं धुमाल की बाढ़ सी आ गयी है, वो अति उच्च डेसीबल में बजाते है जो कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना भी है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्तादेवी का निधन

रायपुर. अग्रवाल समाज के वरिष्ठ समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्तादेवी अग्रवाल (91) का आज शाम निधन हो गया. उनकी अंतिम यात्रा 28 फरवरी को सुबह 10 बजे मौलश्री विहार रायपुर से निकलेगी. उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी श्मशान में किया जाएगा. पिस्ता देवी अग्रवाल समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा,संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता, विष्णु अग्रवाल की भाभी एवं पूरनलाल अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, गणेश अग्रवाल की चाची थी.

लंबे समय से थी बीमार- बता दें कि पिस्तादेवी अग्रवाल लंबे समय से अस्वस्थ थीं. उन्हें उपचार के लिए शहर के बड़े निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां वे कुछ दिन वेंटिलेटर पर थी, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर उन्हें वापस निवास स्थान ले आया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली.

रायपुर में होगा आईपीएल का मुकाबला!.. फ्रेंचाईजी ग्रुप ने किया इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण

रायपुरॅ. राजधानी रायपुर के लोगों में एक बार फिर से क्रिकेट के महाकुम्भ में शामिल होने यानी इंडियन प्रीमियर लीग जैसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग देखने का मौका मिल सकता हैं। जी हाँ.. अगर सबकुछ सही रहा तो 2024 के आईपीएल के मुकाबले रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कराये जा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक मुकाबलों के संभावनाओं को टटोलने आईपीएल टीम के फ्रेंचाइजी ने स्टेडियम का दौरा किया हैं। अब उनके रिपोर्ट का इंतज़ार हैं। किसी भी तरह के सफल मुकाबले के आयोजन में

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी बड़ी भूमिका होगी लिहाजा अगर टीम फ्रेंचाइजी और सरकार के बीच समन्वय सही रहा तो इस साल होने वाले आईपील के मैच रायपुर स्थित दुनिया के चौथे सबसे बड़े शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिल सकता हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हैं क्योंकि आईपीएल के लिए अबतक सिर्फ 17 मुकाबलों के लिए वेन्यू तय किये गये हैं। ऐसे में रायपुर वासियों को उम्मीद हैं कि उन्हें लम्बे वक्त के बाद क्रिकेट का धमाल देखने को मिल सकता हैं। बता दें कि आईपीएल 2024 अगले महीने यानी 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला करेगी। बीसीसीआई के अनुसार, 17 दिनों में 21 मैच खेले जाएंगे जो 22 मार्च से 7 अप्रैल के बीच होंगे। बाकी का शेड्यूल भारत में होने वाले आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा। इस छोटे शेड्यूल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पांच मैच खेलेगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ दो मैच खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों घरेलू मैच विशाखापत्तनम में खेलेगी।

इस संस्करण में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पांड्या 24 मार्च को अपनी पूर्व टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेंगे।

लोकसभा चुनाव तैयारी में जुटी भाजपा, 28 फरवरी को होगी मैराथन बैठकें

रायपुर। लोकसभा चुनाव तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की 28 फरवरी को मैराथन बैठकें होने जा रही है. राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत इन मैराथन बैठकों में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन चुनाव के मद्देनजर अब तक के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करेंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बैठकों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले क्लस्टर प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों, लोकसभा संयोजकों व सह संयोजकों की बैठक होगी. दूसरी बैठक में भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों की टोलियों की बैठक होगी. इसके बाद भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री, संभाग प्रभारियों की बैठक रखी गई है. सबसे अंत में प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक प्रदेश सह प्रभारी नवीन की उपस्थिति में होगी. श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव तैयारियों के दृष्टिगत ये बैठकें काफी अहम हैं, और इनमें चुनावी रणनीति के मार्गदर्शक बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा होगी. इन बिन्दुओं के आलोक में मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन-आशीर्वाद से हासिल ऐतिहासिक जनादेश से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए 'अबकी बार चार सौ पार' का लक्ष्यनिष्ठ संकल्प लेकर चुनावी मैदान में हैं. भाजपा चुनावी तैयारियों में काफी तेजी से आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पराजित मनोबल और हताशा की शिकार दिखाई पड़ रही है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.